My Notes

राष्ट्रीय

अग्नि-4 मिसाइल का सफल परीक्षण:

ओडिशा के बालासोर से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाली परमाणु क्षमता युक्त मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया। इस न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण कर भारत ने दुश्मन देशों को कड़ा संदेश दिया है। भारत की सबसे घातक उपमहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल अग्नि-5 के परीक्षण के हफ्ते भर के भीतर यह दूसरा परीक्षण है। अग्नि-5 उपमहाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइल समूचे उत्तरी चीन को तबाह करने में सक्षम हैं।

अग्नि-4 की खास बातें:

1. सतह से सतह पर मार करने में सक्ष्म स्वदेशी मिसाइल अग्नि-4 में द्विचरणीय शस्त्र प्रणाली है। यह 20 मीटर लंबी और 17 टन वजनी है। अग्नि-4 मिसाइल में पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर लगे हैं।
2. इसकी आधुनिकतम विशेषताएं उड़ान के दौरान आने वाली खामियों से खुद को ठीक एवं दिशा निर्देशित करना हैं। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बनाया है।
3. इस मिसाइल में सॉलिस प्रॉप्लशन के दो चरणों हैं, जिसके चलते मिसाइल की कार्यक्षमता 3000 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर भी प्रभावित नहीं होगी।
4. इससे पहले दिसंबर 2016 के अंतिम सप्ताह में करीब 6000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण हुआ था। अग्नि-5 की जद में पाकिस्तान, चीन और यूरोप समेत आधी दुनिया है। अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन के बाद भारत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) बनाने वाला 5वां देश है। अग्नि-5 का ये चौथा परीक्षण था। पहली बार 2012 में इस मिसाइल का परीक्षण किया गया

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला:

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि धर्म, जाति, भाषा व संप्रदाय के आधार पर वोट मांगना चुनाव कानूनों के तहत भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। प्रधान न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली सात जजों की संविधान पीठ ने 4 अनुपात 3 के बहुमत से यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला कई याचिकाओं और हिंदुत्व की व्याख्या से जुड़े दो केस को जोड़ते हुए की गई सुनवाई के बाद सुनाया।

इन दो केस को जोड़ा:

1. मुंबई के सांताक्रूज से 1990 में भाजपा के टिकट पर अभिराम सिंह विधानसभा चुनाव जीते थे। उनके चुनाव को बॉम्बे हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया था। 16 अप्रैल, 1992 को सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने सिंह की अपील को पांच सदस्यीय पीठ को सौंप दिया था, जो कि ऐसे ही मामले पर विचार कर रही थी।
2. 30 जनवरी 2014 को पीठ को बताया गया कि ऐसा ही एक मामला नारायण सिंह विरुद्ध सुंदरलाल पटवा के मामले में भी उठा था। तब इसे पांच सदस्यीय पीठ ने सात सदस्यीय पीठ को सौंपा था।
3. सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2014 में अभिराम सिंह का केस अन्य के साथ जोड़ते हुए सात सदस्यीय पीठ को सौंपने का आदेश दिया था।

क्या है?

1. चुनाव में भ्रष्ट आचरण से संबंधित जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123(3) में उल्लेखित शब्द 'उसके धर्म' के आशय का खुलासा करते हुए कोर्ट ने कहा, इसका आशय वोटर, प्रत्याशी व उनके एजेंटों के धर्म व जाति से है। यानी कोई भी प्रत्याशी या उनके एजेंट मतदाताओं से इन आधारों पर वोट नहीं मांग सकते। कोर्ट ने इससे संबंधित चुनाव कानूनों की व्याख्या से संबंधित याचिका पर फैसला 27 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था।
2. सात सदस्यीय संविधान पीठ के अल्पमत के तीन जजों-जस्टिस यूयू ललित, ए. के. गोयल व डीवाई चंद्रचूड़ की राय थी 'उसके धर्म' से आशय सिर्फ प्रत्याशी के धर्म से है।
3. पीठ के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश जस्टिस ठाकुर समेत चार जजों-जस्टिस एमबी लोकुर, एसए बोबडे, एलएन राव ने कहा, ऐसे मामलों पर विचार करते हुए धर्म निरपेक्षता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

'खांदेरी' नवसेना में शामिल:

कलवरी श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी आईएनएस खांदेरी का मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में जलावतरण किया किया गया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे जलावतरण समारोह की अध्यक्षता की। जलावतरण में पनडुब्बी उस पंटून से अलग होगी, जिस पर इसे तैयार किया जा रहा है। इसके बाद इसकी अंतिम सेटिंग तैरने लगेगी। ये पनडुब्बी एंटी मिसाइल से लेकर परमाणु झमता से लैस है। गौरतलब है कि कलवरी को पहले ही लॉन्च किया जा चुका है और अभी इसका ट्रायल चल रहा है, जिसके खत्म होने पर इसे नौसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इस सीरीज की पहली पनडुब्बी कलवरी को पिछले

साल अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसे दिसंबर तक शामिल करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह नहीं हो पाया। भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जो परंपरागत पनडुब्बियों का निर्माण करते हैं। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत एमडीएल में फ्रांस के मैसर्स डीसीएनएस के साथ मिलकर छह पनडुब्बियों का निर्माण किया जा रहा है।

क्या है?

1. कलवरी और खंडेरी पनडुब्बियां आधुनिक फीचर्स से लैस है। यह दुश्मन की नजरों से बचकर सटीक निशाना लगा सकती हैं। इसके साथ ही टॉरपीडो और एंटी शिप मिसाइलों से हमले भी कर सकती हैं।
2. भारतीय नौसेना की पनडुब्बी शाखा इस साल आठ दिसंबर को 50 साल पूरे करेगी। आठ दिसंबर 1967 को नौसेना में पहली पनडुब्बी आइएनएस कलवरी शामिल होने के उपलक्ष्य में हर साल इस दिन को पनडुब्बी दिवस के तौर पर मनाया जाता है।
3. सात फरवरी 1992 को पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी आइएनएस शाल्की के शामिल होने के साथ ही भारत पनडुब्बी बनाने वाले देशों के समूह में शामिल हो गया था। इसके बाद आइएनएस शांकुल को 28 मई 1994 को लॉन्च किया गया।
4. खांदेरी नाम मराठा बलों के द्वीपीय किले के नाम पर दिया गया है। इसकी 17वीं सदी के अंत में समुद्र में मराठा बलों का सर्वोच्च अधिकार सुनिश्चित करने में बड़ी भूमिका थी।
5. इस सबमरीन से टारपीडो के जरिए भी दुश्मन पर अटैक किया जा सकेगा। सबमरीन पानी में हो या सतह पर दोनों ही स्थितियों में इसकी ट्यूब प्रणाली एंटी सिप मिसाइल लॉन्च कर सकती है। सबमरीन को ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो हर जगह चल सके।
6. इस सबमरीन के जरिए नेवल टास्क फोर्स भी दुश्मनों पर कभी भी कहीं से भी हमला करने में सक्षम होगी। इस पनडुब्बी को माड्यूलर कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रख कर बनाया गया है। इसके तहत सबमरीन को कई सेक्शन में डिवाइड किया जा सकता है।

भारतीय समय में जोड़ा गया एक सेकेंडः

पृथ्वी की घूर्णन घड़ी (रोटेटिंग वॉच) से तालमेल स्थापित करने के लिए 1 जनवरी 2017 को पांच बजकर 29 मिनट 59 सेकेंड पर भारतीय घड़ी में एक सेकेंड जोड़ा गया। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एनपीएल) में आणविक घड़ी (मॉलिक्यूलर क्लॉक) में जब 23 बजकर 59 मिनट और 59 सेकेंड हुआ तब धरती के घूर्णन में कमी के साथ तालमेल कायम करने के लिए वर्ष 2017 में एक सेकेंड जोड़ने का कार्यक्रम तय किया गया।

क्या है?

1. वैसे तो एक सेकेंड जोड़ने से रोजमर्रा की जिंदगी बमुश्किल कोई असर पड़ेगा लेकिन यह उपग्रह के नौवहन, खगोल विज्ञान और संचार के क्षेत्र में काफी मायने रखता है।
2. पृथ्वी और अपनी धुरी पर उसके घूर्णन नियमित नहीं हैं, क्योंकि कभी-कभी यह भूकंप, चंद्रमा के गुरूत्व बल समेत विभिन्न कारकों के चलते तेज तो कभी कभी धीमे हो जाते हैं। चंद्रमा के गुरूत्व बल से सागरों में लहरें उठती हैं।

दुनिया की शीर्ष 5 तोपों में शामिल हुई 'धनुष':

सरहद की निगरानी बोफोर्स की जगह 'धनुष' तोप के हवाले होगी। कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्टरी में तैयार होने वाली इस स्वदेशी तोप की मारक क्षमता बोफोर्स के मुकाबले 18 किलोमीटर ज्यादा है। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्टरी ने डीआरडीओ संग मिलकर अत्याधुनिक तोप का बनाई है। कई मायनों में बेहतर 'धनुष' तोप की बैरल रेंज 46 किलोमीटर तक है, जो दुनिया की किसी भी तोप को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है।

दुनिया की शीर्ष पांच तोपों में शामिल

1. बोफोर्स बीओ-5 (स्वीडन)
2. एम 46-एस (इजरायल)
3. जीसी 45 (कनाडा)
4. नेक्सटर (फ्रांस)
5. धनुष (भारत)

क्या है?

1. 'धनुष' का नया बैरल आठ मीटर लंबा है। यह दुनिया के सबसे लंबे बैरल वाली तोपों में से एक है। आठ मीटर लंबी तोप सिर्फ अमेरिका, इजरायल और रूस के पास है। खास बात यह है कि आठ मीटर लंबे धनुष के बैरल को बोफोर्स तोप में भी लगाया जा सकता है।
2. 'धनुष' देश की पहली तोप हैं, जिसमें 90 फीसदी कलपुर्जे भारत में बने हैं। शेष इन हिस्सों को भी स्वदेश में तैयार करने का काम चल रहा है। सेना को इसे सौंपने से पहले इससे 2000 राउंड फायर किए गए।

3. सेना ने ऑर्डिनेंस फैक्टरी कानपुर को 414 'धनुष' का आर्डर दिया है। ऑर्डिनेंस फैक्टरी को एक तोप बनाने में 15-20 दिन का समय लगता है। पहले चरण में 114 'धनुष' तैयार कर देनी हैं, जिनमें से कुछ तोपें दी जा चुकी हैं। तैयार होने वाली तोपों में धनुष और उसका उन्नत संस्करण भी शामिल है।
4. जहां जैसी जरूरत होगी सेना उसका इस्तेमाल कर सकेगी। यह संख्या आगे बढ़ने की उम्मीद है। धनुष 03 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस तक काम करने में सक्षम है। धनुष का बैरल रूसी और यूरोपीय तकनीक को मिलाकर तैयार किया गया है, जो किसी भी सूरत में फटेंगे नहीं।

धनुष की ताकतः

1. 2692 किलोग्राम बैरल का वजन
2. 46 किलोमीटर तक मारक क्षमता
3. 2 फायर प्रति मिनट में दो घंटे तक लगातार गोले दागने में सक्षम
4. 3 फायर प्रति मिनट में डेढ़ घंटे तक लगातार दागने में सक्षम
5. 46.5 फायर प्रति मिनट करने की क्षमता
6. 12 फायर प्रति मिनट करने की क्षमता

इसरो एक साथ 103 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगाः

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) फरवरी के पहले हफ्ते में अपने प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी37 का इस्तेमाल कर रिकॉर्ड 103 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी दक्षिण एशियाई उपग्रह परियोजना मार्च में शुरू होगी । फरवरी में जिन 100 से ज्यादा उपग्रहों का प्रक्षेपण होना है वे अमेरिका और जर्मनी सहित कई अन्य देशों के हैं।

क्या है?

1. इसरो के लिक्विड प्रॉपल्शन सिस्टम्स सेंटर के निदेशक एस. सोमनाथ ने बताया, एक ही साथ 100 से ज्यादा उपग्रहों का प्रक्षेपण कर हम शतक बनाने जा रहे हैं।
2. सोमनाथ ने बताया कि इससे पहले इसरो ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में एक साथ 83 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई थी, जिसमें से 80 विदेशी उपग्रह थे। लेकिन इनमें 20 और विदेशी उपग्रहों के जुड़ जाने के कारण प्रक्षेपण की तारीख करीब एक हफ्ते आगे बढ़ा दी गई। ये प्रक्षेपण अब फरवरी के पहले हफ्ते में होगा।
3. उन्होंने उन देशों की संख्या के बारे में नहीं बताया जो इस मिशन में अपने उपग्रहों का प्रक्षेपण करेंगे । हालांकि, उन्होंने कहा कि इसमें अमेरिका और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं । सोमनाथ ने कहा, ये 100 सूक्ष्म-लघु उपग्रह होंगे, जिनका प्रक्षेपण पीएसएलवी-37 के इस्तेमाल से किया जाएगा। पेलोड का वजन 1350 किलोग्राम होगा, जिसमें 500-600 किलोग्राम उपग्रहों का वजन होगा।
4. भारत के अंतरिक्ष इतिहास में यह प्रक्षेपण एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर पहले कभी प्रक्षेपण नहीं हुए। पिछले साल इसरो ने एक ही बार में 22 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था और फरवरी के पहले हफ्ते में होने वाले प्रक्षेपण में उपग्रहों की संख्या करीब पांच गुना ज्यादा होगी।
5. इसरो के असोसिएट निदेशक एम नागेश्वर राव ने बताया कि दक्षिण एशियाई उपग्रह जीसैट-9 का हिस्सा होगा, जिसे इस साल मार्च में प्रक्षेपित किया जाएगा। इस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण दिसंबर 2016 में होना था, लेकिन इसमें थोड़ी देर हो गई क्योंकि कुछ अन्य उपग्रहों का प्रक्षेपण पहले किया जाना था।
6. इस परियोजना में अफगानिस्तान को शामिल करने के लिए उससे चल रही बातचीत अंतिम चरण में है। पहले दक्षेस उपग्रह के तौर पर ज्ञात रही यह परियोजना भारत के पड़ोसी देशों के लिए तोहफा मानी जा रही है। पाकिस्तान इस परियोजना पर कड़ा विरोध जताता रहा है। पाकिस्तान इसे दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय फोरम के बैनर तले प्रक्षेपित कराना चाह रहा था। बाद में वह परियोजना से अलग हो गया। भारत के अलावा, इस उपग्रह से श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को फायदा मिलेगा।

संपत्ति पर कानूनी अधिकार को लेकर SC ने दिया बड़ा फैसलाः

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि संपत्ति की देखभाल करने वाला केयरटेकर या नौकर का संपत्ति में कोई अधिकार सृजित नहीं हो सकता चाहे वह उसमें लंबे समय से ही क्यों न बना हो। जस्टिस दीपक मिश्रा और पीसी घोष की पीठ ने यह आदेश देते हुए नौकर को मकान से बेदखल करने का फैसला दे दिया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी को संपत्ति में बिना कुछ लिए रहने का अनुमति दी गई चाहे दशकों की अवधि ही क्यों न हो उसका संपत्ति में कोई अधिकार सृजित नहीं होगा।
2. केयरटेकर, नौकर, चौकीदार लंबे समय तक रहने के आधार पर संपति में कोई अधिकर नहीं जता सकते। नौकर या केयरटेकर को मांगने पर संपत्ति मालिक को सौंपनी ही पड़ेगी। कोर्ट का संरक्षण उसे तभी मिल सकता है जब उसके पास उसके पक्ष में वैध किराया, लीज या लाइसेंस एग्रीमेंट हो।
3. केयर टेकर या नौकर संपत्ति का कब्जा मालिक की अनुमति के आधार पर रखता है। इसमें उसका कोई अधिकार नहीं बनता चाहे वह कितने लंबे समय से उसमें क्यों न रह रहा हो।
4. सर्वोच्च अदालत ने कोर्ट ने यह फैसला बंबई के एक मामले में दिया जिसमें मालिकों ने एक परिवार को संपत्ति बिना कुछ पैसा लिए आपसी प्रेम के कारण रहने के लिए दे दी थी। लेकिन जब मालिकों ने 16 वर्ष बाद संपत्ति की मांग की तो उसे खाली करने से मना कर दिया।
5. इसके खिलाफ परिवार पहले निचली अदालत में गया जहां से उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया और हाईकोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया का इसतेमाल किए परिवार को संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

104 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस -2017:

तिरुपति के वेंकटेश्वर विश्व विद्यालय परिसर में 3 जनवरी से 7 जनवरी तक आयोजित 104 वें 'प्राइड ऑफ इंडिया साइंस एक्सिपो -2017' में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) हिस्सास ले रहा है। पांच दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम को 104 वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस-2017 (आईएससी -2017) के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था।

क्या है?

1. इस बड़े विज्ञान प्रदर्शनी में डीआरडीओ मंडप का उद्घाटन 3 जनवरी, 2017 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री चंद्र बाबू नायडू ने किया था। श्री नायडू ने इस दौरान डीआरडीओ द्वारा लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का दौरा कर संगठन के विभिन्नि उत्पादों एवं प्रौद्योगिकी में अपनी रुचि भी दिखाई।
2. इसी स्थल पर 'फ्रंटरियर ऑफ डिफेंस रिसर्च' नाम से एक समापन सत्र का भी आयोजन 04 जनवरी, 2017 को किया गया।
3. इस प्रदर्शनी में डीआरडीओ की 40 प्रयोगशालाएं भाग ले रही हैं जो 'मेक इन इंडिया' की भावना को प्रदर्शित करतीं हुई आत्मानिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव की कहानियों का वर्णन कर रही हैं। आउटडोर उत्पादों की प्रदर्शनी में लंबी दूर तक जमीन से जमीन पर मार करने वाली अग्नि-5, आकाश शस्त्र प्रणाली, शौर्य मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल, दूर संवेदी प्रणाली से संचालित होनेवाला दक्ष रोबोट मुख्य आकर्षण हैं।
4. इनडोर उत्पादों की प्रदर्शनी में एईडब्यूवर एंड सी, एलसीए तेजस, रुस्तम, यूएवी, उन्नत हल्केग वजन का तापिडो (टीएएल), मल्टी मोड हैंडग्रेनेड, एनबीसी सूइट, एंटी माइन्सण बूट, माइक्रो वेव पावर मोड्यूल, एस-बैंड एमएसएस टर्मिनल, इंटेग्रेटेड मल्टीफंक्शन साइट (आईएमएफएस) प्रीएम्पटर सिस्टम, उष्मसन तंत्र-सहित अनेक जीव विज्ञान संबंधी उत्पाद भी शामिल हैं। दर्शकों और छात्रों के बीच डीआरडीओ का मंडल आकर्षण का केद्र बना हुआ है।

पं बंगाल में तैनात होगा राफेल का पहला दस्ता:

भारत ने चीन से सटी पूर्वी सीमाओं को मजबूत करने के लिए लड़ाकू विमान राफेल की तैनाती की तैयारी शुरू कर दी है। वायु सेना 2019 के आखिर तक पहले 18 राफेल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा बेस पर तैनात करेगी। भारत इस लड़ाकू विमान की तैनाती उस नीति के तहत कर रहा है, जिसके तहत चीन के खिलाफ पारंपरिक और न्यूक्लियर, दोनों तरह के हमलों के लिए मजबूत किया जा सके।

क्या है?

1. भारत पहले ही सुखोई-30MKI फाइटर प्लेन की तैनाती असम के तेजपुर और छाबुआ में कर चुका है। अब भारतीय वायु सेना ने इस योजना के तहत 2019 के अंत तक 18 राफेल लड़ाकू विमानों को पश्चिम बंगाल के हाशिमपुरा बेस पर तैनात किया जाएगा।
2. भारत ने इस योजना को अमल में लाने का फैसला ऐसे वक्त में किया है, जब परमाणु क्षमता वाले अग्नि-4 और अग्नि-5 मिसाइल के ट्रायल अंतिम दौर में हैं। अग्नि-3 को पहले ही सेना में शामिल किया जा चुका है।

3. पिछले साल सितंबर में भारत ने इस विमान की खरीद के लिए फ्रांस के साथ 59000 करोड़ रुपये की डील की थी। इसके तहत, 2022 के मध्य तक वायुसेना को 36 राफेल विमान कई चरणों में मिलेंगे। भारतीय हालात के मद्देनजर इनमें कुछ अन्य फीचर्स जोड़ने की डिमांड की गई है।
4. इनमें ऊंचाई वाले इलाकों में 'कोल्ड स्टार्ट' की सुविधा भी शामिल है। राफेल 9.3 टन के हथियार ढोने में सक्षम है। राफेल हवाई सुरक्षा से लेकर जमीनी हमले से जुड़े अभियानों के लिए बेहद भरोसेमंद है।
5. 'हाशिमपुरा एयरबेस' पर फिलहाल मिग-27 विमान तैनात हैं, जो अगले दो से तीन साल में रिटायर कर दिए जाएंगे।
6. मिग-27 को राफेल रिप्लेस करेगा। राफेल बनाने वाली कंपनी के प्रतिनिधियों ने हाल ही में हाशिमपुरा बेस का दौरा किया। इसका मकसद इस जेट के मेंटेनेंस और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर के हालात की समीक्षा करना था। राफेल के नियुक्त करने लिए जिन जगहों को चुनाव किया है, उसमें उत्तर प्रदेश का सरस्वा एयरबेस शामिल है।

अब सौतेले मां-बाप भी बच्चे को ले सकेंगे गोदः

नए नियमों के तहत अब सौतेले मां-बाप भी अपने सौतेले बच्चे को कानून गोद ले सकते हैं। वैध कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए बच्चों को गोद लेने वाले राष्ट्रीय निकाय से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। बच्चे गोद लेने की नई नियमावली 16 जनवरी से प्रभावी हो जाएगी। इसके तहत रिश्तेदार भी बच्चों को गोद ले सकेंगे।

क्या है?

1. सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के सीईओ ले. कर्नल दीपक कुमार ने बताया कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, जिसमें सौतेले मां या बाप का सौतेली संतान से रिश्ता परिभाषित किया गया हो। इसलिए अब तक सौतेली संतान का सौतेले पिता की संपत्ति पर कोई कानूनी हक नहीं है।
2. इसी तरह सौतेली संतान को बुढ़ापे में अपने सौतेले पिता या सौतेली मां की देखभाल की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। ले. कर्नल दीपक कुमार ने कहा कि इस रिक्तता को भरने की कोशिश की जा रही है। कारा केंद्र सरकार का निकाय है, जो देश भर में गोद लेने के नियमों के पालन और निगरानी का काम करता है।
3. इससे पूर्व, केवल अनाथ या छोड़ दिए गए या बरामद हुए बच्चे को ही गोद लिए जाने की अनुमति दी जाती थी। लेकिन अब सरकार ने इस परिभाषा को विस्तार दिया है। अब में रिश्तेदार के बच्चे और पति या पत्नी के पूर्व विवाह से हुई संतान को भी कानूनी दायरे में लाया गया है। इसके अलावा, जैविक मां-बाप भी कानूनन अपने बच्चे को गोद दे सकते हैं।

20वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलनः

भारत सरकार का प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग तथा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिल कर 9-10 जनवरी, 2017 के दौरान विशाखापट्टनम में 20वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है। इस कार्यक्रम में सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षाविद् और उद्योग जगत एवं स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे।

क्या है?

1. इस दौरान वर्ष 2016-17 के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं से सम्बद्ध 12 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक श्रेणी में स्वर्ण और रजत पुरस्कार शामिल होंगे। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। सम्मेलन दो दिन तक चलेगा, जिसमें चुने हुए विषयों और उप विषयों से संबंधित सत्र, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य संबंधित गतिविधियां शामिल होंगी।
2. उद्घाटन सत्र के बाद सम्मेलन के मुख्य विषय ''डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन'' के बारे में सत्र का आयोजन किया जाएगा। पूर्ण सत्र के दौरान विशेष उप-विषयों जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और डेटा एनेलेटिक्सः आईओटी के इस्तेमाल पर विचार-विमर्श तथा सरकारी प्रक्रियाओं के रूपांतरण में डेटा एनेलेटिक्स और सर्विस डिलीवरी पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त साइबर सुरक्षा नीति, अंतिम मील तक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रौद्योगिकी के नेतृत्व में नकदी लेन-देन और आधार के जरिये नकदी रहित भुगतान जैसे विषय भी शामिल किए जाएंगे।

सरोगेसी से मां बनने वाली कर्मचारी भी मातृत्व अवकाश की पात्रः

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मां बनने वाली शासकीय महिला कर्मचारी को सरकार के नियमानुसार मातृत्व अवकाश की पात्रता है। न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल की एकलपीठ ने दुर्ग जिले की एक व्याख्याता साधना अग्रवाल की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि प्राकृतिक, बायोलॉजिकल तथा सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मां बनने पर इनमें भेद-भाव नहीं किया जा सकता।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मातृत्व तथा बच्चे को बेहतर विकास का अधिकार भी शामिल है।
2. एकलपीठ ने अपने फैसले में देश की शीर्ष अदालत के कुछ फैसलों का हवाला देते इस मामले में जुड़वां बच्चे की मां बनने वाली याचिकाकर्ता के मातृत्व अवकाश के आवेदन को खारिज करने को पूरी तरह अनुचित बताया।
3. याचिका में कहा गया कि उन्होंने शादी के 26 साल तक नि:संतान रहने के कारण पति के साथ मिलकर सरोगेसी प्रक्रिया के माध्यम से मां बनने का निर्णय लिया। गत 27 मार्च को इंदौर के एक अस्पताल में सेरोगेट मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिन्हें याचिकाकर्ता को तत्काल सौंप दिया गया। इस पर आठ लाख रुपये खर्च हुए।
4. याचिकाकर्ता ने घर लौट कर मातृत्व अवकाश के लिए आवेदन दिया, लेकिन चार महीने बाद उनका आवेदन निरस्त करते हुए कहा गया कि सरोगेसी से मां बनने वालों के लिए मातृत्व अवकाश के लिए कोई नियम नहीं है।

कावेरी विवाद: SC लगाया जुर्माना:

कावेरी जल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को कावेरी नदी से दो हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति तमिलनाडु को करने का निर्देश जारी किया था, जिसका पालन नहीं किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार पर जुर्माना लगाते हुए इसकी भरपाई करने का निर्देश जारी किया है।

क्या है?

1. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को बतौर जुर्माना दो हजार चार सौ अस्सी करोड़ रूपए देगा।
2. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से एक हफ्ते में गवाहों की लिस्ट मांगी है, साथ ही उन गवाहों के एफिडेविड जमा करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।
3. कावेरी जल विवाद का इतिहास काफी पुराना है। हंगामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राज्यों की सरकार से समाधान निकालने का आदेश जारी किया।

राजनैतिक दलों को आयकर से छूट के खिलाफ SC में याचिका खारिज:

सुप्रीमकोर्ट ने राजनैतिक दलों को आयकर से छूट देने के कानून को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये सरकार का नीतिगत मामला है और इससे किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता। मुख्य न्यायाधीश जे. एस. खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि राजनैतिक दलों को आयकर से छूट देना सरकार की कार्यकारी कार्रवाई है और इससे संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन नहीं होता न ही इससे आयकर या जनप्रतिनिधित्व कानून के किसी प्रावधान का हनन होता है। इसमें सुप्रीमकोर्ट दखल नहीं दे सकता।

क्या है?

1. वकील एमएल शर्मा ने अपनी याचिका में राजनैतिक दलों को चंदे में प्राप्त रकम को आयकर से छूट देने के कानून को चुनौती देते हुए कहा था कि राजनैतिक दलों को आयकर में छूट दी गई है जबकि सामान्य नागरिकों को ऐसी छूट नहीं है।
2. याचिका में राजनैतिक दलों को आयकर कानून से छूट दिये जाने के प्रावधान 13ए को चुनौती दी गई थी साथ ही राजनैतिक दलों के खिलाफ गैरकानूनी चंदे का मामला दर्ज कर कोर्ट की निगरानी में एसआइटी या सीबीआइ से जांच कराए जाने की मांग की गयी थी।
3. जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29 को भी रद करने की मांग की गई थी। लेकिन कोर्ट ने सारी दलीलें ठुकराते हुए याचिका खारिज कर दी। यह याचिका नोट बंदी के बाद दाखिल की गई थी और दिसंबर में ही कोर्ट से इस पर जल्दी सुनवाई की मांग की थी।
4. आयकर कानून में राजनैतिक दलों को आयकर अदा करने से पूरी तरह छूट है। इसके अलावा 20000 तक की रकम पर तो उन्हें हिसाब भी नहीं देना पड़ता।
5. याचिका में आरोप लगाया गया था कि राजनैतिक दलों ने पुराने नोट खाते में जमा किये हैं और पैसा निकाला है लेकिन आयकर में छूट होने के कारण उनके खातों की जांच नहीं हो रही है। लेकिन गत 23 दिसंबर को सुप्रीमकोर्ट ने मामले पर जल्दी सुनवाई करने की मांग ठुकरा दी थी कोर्ट ने कहा कि जिस कानून को याचिका में चुनौती दी गई है वह पचास साल पुराना है। ऐसे में मामले पर तत्काल सुनवाई की जरूरत नहीं है। उस दिन कोर्ट ने मामले पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि तय कर दी थी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

दत्तक ग्रहण विनियमन देश में प्रभावी:

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 68 (सी) के तहत अधिदेशित केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (सीएआरए) द्वारा तैयार किया गया दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 को सरकारी प्रेस द्वारा 4 जनवरी 2017 को अधिसूचित कर दिया गया है और ये विनियमन 16 जनवरी, 2017 से प्रभावी होंगे। दत्तक ग्रहण विनियमन, 2017 दत्तक ग्रहण दिशा निर्देश की जगह लेंगे। दत्तक ग्रहण विनियमन की रूप रेखा दत्तक ग्रहण एजेंसियों और भावी दत्तक माता पिता (पीएपी) सहित सीएआरए और अन्य हितधारकों के सामने आ रहे मुद्दों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बनायी गयी है। यह भविष्य में गोद लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के द्वारा देश में गोद लेने के कार्यक्रम को और मजबूत बनाएगा। पारदर्शिता, बच्चों के प्रारंभिक विसंस्थागतकरण, माता-पिता के लिए सुविज्ञ विकल्प, नैतिक प्रथाओं और गोद लेने की प्रक्रिया में सख्ती से परिभाषित समयसीमा दत्तक ग्रहण विनियमन के प्रमुख पहलू हैं।

दत्तक ग्रहण के विनियमन 2017 की मुख्य विशेषताएं:

1. विनियमनों में देश के भीतर और विदेशों में रिश्तेदारों द्वारा गोद लेने की प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है।
2. गृह अध्ययन रिपोर्ट की वैधता दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दी गई है।
3. निर्दिष्ट बच्चे को आरक्षित करने के बाद मिलान और स्वीकृति के लिए घरेलू पीएपी को उपलब्ध समयसीमा को वर्तमान पंद्रह दिनों से बढ़ाकर बीस दिन कर दिया गया है।
4. जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) के पास व्यावसायिक रूप से योग्य या प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक पैनल होगा।
5. न्यायालय में दायर किए जाने वाले मॉडल दत्तक ग्रहण आवेदनों समेत विनियमनों से संलग्न 32 अनुसूचियां हैं और यह न्यायालय के आदेश प्राप्त करने में वर्तमान में लगने वाली देरी में काफी हद तक कमी लाएंगी।

अंतर्राष्ट्रीय

20 साल पुरानी क्यूबाई आव्रजक नीति खत्म:

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने दो साल पुरानी 'वेट फुट ड्राई फुट' नीति को खत्म कर दिया है। इस नीति के तहत अमेरिका पहुंचे क्यूबाई आव्रजकों को एक वर्ष बाद वैधानिक स्थायी निवासी बनने की अनुमति दी जाती थी।

क्या है?

1. ओबामा प्रशासन के आखिरी दिनों में उठाए गए इस कदम को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्यूबा लंबे समय तक अमेरिका का दुश्मन रहा है। संबंध सामान्य बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण उपाय किया गया है। ओबामा ने कहा, गृह सुरक्षा विभाग तथाकथित 'वेट फुट, ड्राई फुट' को खत्म कर रहा है।
2. यह नीति 20 साल से ज्यादा समय पहले लागू की गई थी। यह नीति एक अलग युग में तैयार की गई थी। 'उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट देश के साथ स्थिति सामान्य बनाने के लिए अमेरिका महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।'
3. यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अमेरिका में गैरकानूनी रूप से प्रवेश करने वाले क्यूबाई नागरिक को जगह नहीं मिलेगी। मानवीय सहायता के योग्य नहीं पाए जाने पर क्यूबाई नागरिक को बाहर किया जाएगा।

पाकिस्तान में हिंदू विवाह अधिनियम पर सीनेट की मुहर:

पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को नए साल का उपहार देते हुए मानवाधिकार पर सीनेट की कार्य समिति ने ऐतिहासिक 'हिंदू विवाह अधिनियम' को मंजूरी दे दी है। इससे पहले पिछले सितंबर में इसे नेशनल असेंबली की मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून के बन जाने से पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिल जाएगी।

क्या है?

1. हिंदुओं को मुस्लिम के 'निकाहनामे' की तरह शादी के प्रमाण के तौर पर 'शादीपरत' दिया जाएगा।
2. अलग होने के लिए हिंदू दंपती अदालत से तलाक का अनुरोध भी कर सकेंगे। तलाक ले चुके व्यक्ति को इस कानून के तहत फिर से विवाह का अधिकार दिया गया है। किसी महिला को पति की मृत्यु के छह महीने नेशनल असेंबली के अल्पसंख्यक सदस्य रमेश कुमार ने 'हिंदू विवाह अधिनियम' को सीनेट की मंजूरी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि आज हमें पाकिस्तानी हिंदू होने पर गर्व हो रहा है।

दक्षिणी चीन सागर में नौसेना अभ्यास:

चीनी नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में विमान वाहक पोत के अभ्यास की पुष्टि की है। इससे पहले ताईवान ने बताया था कि चीन का विमान वाहक पोत दोनों देशों के बीच तनाव के बावजूद 90 नौटिकल मील तक चला गया था।

क्या है?

1. सोवियत निर्मित लिओनिंग विमान वाहक पोत ताइवान के पूर्वी तट तक पहुंच गया था वहीं चीन ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत सामान्य अभ्यास का हिस्सा बताया है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA) 7463950774, (DIBRUGARH) 7086798370 www.ksgindia.com

2. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना ने आधिकारिक रूप से कहा कि कल मुश्किल समुद्री परिस्थितियों के बीच जे-15 लड़ाकू विमान ने अभ्यास किया था लेकिन अधिकारियों ने अभ्यास की सटीक स्थान के बारे में जानकारी नहीं दी।
3. दक्षिणी चीन सागर पर चीन समेत उसके पड़ोसी देश ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताईवान और वियतनाम भी अपना हिस्सा जताते हैं।

चीन की दीवार से भी मोटी है धोलाविरा की दीवार:

2004 की आपदा के बाद हर भारतीय सुनामी शब्द से परिचित होगा। इस आपदा में देश की पूर्वी तट पर विनाशलीला का खेल देखा गया और हजारों की मौत हो गयी थी। लेकिन गोवा में राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं का कहना है कि करीब 5000 साल पहले हड़प्पन संस्कृति के भारतीय नागरिक सुनामी से अच्छी तरह से अवगत थे और अपनी सुरक्षा के लिए उपाय भी किए थे। गुजरात में हड़प्पन संस्कृति के शहर धोलाविरा में 18 मीटर मोटी दीवार इस बात का गवाह है।

क्या है?

1. भारत में हड़प्पन संस्कृति का दूसरा बड़ा और सबसे अच्छे तरीके से अनेकों डिविजनों के साथ बनाया गया शहर धोलाविरा है, जिसमें कई नए फीचर्स हैं जो अब तक अज्ञात हैं। उनके रिपोर्ट के अनुसार, धोलाविरा के वास्तु में दुर्ग, मध्यम शहर और निचला शहर के बीच बड़ी दीवार से अलग किया गया है।
2. अपेक्षा से अधिक मोटी दीवार से यह अनुमान लगाया गया है कि धोलाविरा के प्राचीन निवासी सुनामी से होने वाली तबाही से अवगत थे। शोधकर्ताओं के अनुसार, प्राचीन भारतीयों ने यह मोटी दीवार सुरक्षा के लिए नहीं बनायी होगी। धोलाविरा छोटी नदियों के किनारे स्थित है उत्तर में मानसर और दक्षिण में मानहर।
3. चीन की विशाल दीवार का बेस भी केवल 9 मीटर मोटाई वाला है और टॉप 3.7 मीटर। दूसरी ओर समुंदर से नजदीक होने के कारण धोलाविरा पर सुनामी जैसी आपदा का खतरा बना हुआ रहता है।
4. भारत के पश्चिमी तट पर समुद्री स्तर में बदलाव होना निश्चित है और 4000 साल पहले समुद्री स्तर अभी की तुलना में कहीं अधिक होगा। 5000 साल पहले भारत-पाकिस्तान अलग नहीं थे। मकरन तट पर होने के कारण धोलावीरा सुनामी का एक्टिव बेल्ट है। जहां अतीत में कई सुनामी आ चुकी हैं।
5. शोध के अनुसार गुजरात तट पर आने वाली सुनामी की ऊंचाई 2 से 10 मीटर की होती है। 2000 साल पहले गुजरात के तट पर 3.5 मीटर ऊंची सुनामी की लहरें आयी थीं। हड़प्पन इस खतरे से अवगत और सतर्क थे इसलिए ही धोलाविरा में इतने विशाल दीवार बनाए गए होंगे।

नेपाल में संविधान संशोधन विधेयक:

सीपीएम यूएमएल के नेतृत्व में नेपाल के मुख्य विपक्षी गठबंधन ने राजधानी में विशाल विरोध-प्रदर्शन की शुरूआत की है। इस गठबंधन की मांग है कि सरकार संविधान संशोधन विधेयक बिल को वापस ले, जिसका उद्देश्य मधेसी पार्टियों के आंदोलन की मांगों को स्वीकृति देना है। नौ पार्टियों के गठबंधन को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री प्रचंड को अपनी ताकत दिखाने के लिए राजधानी में 1 लाख से अधिक कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे।

क्या है?

1. इस रैली का उद्देश्य सरकार पर इस बात के लिए दवाब बनाना है कि वह संविधान संशोधन विधेयक को वापस ले।
2. सत्तासीन सीपीएन माओवादी सेंटर और नेपाली कांग्रेस का गठबंधन इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल सके तांकि मधेशियों की मांगों को पूरी किया जा सके। सरकार के खिलाफ इस विरोध प्रदर्शन में आठ अन्य छोटी लेफ्ट पार्टियों सहित सीपीएन-एमएल और नेपाल वर्कर्स तथा पीसेंट पार्टी का समर्थन भी प्राप्त है।
3. पिछले सितंबर में नया संविधान अपनाया गया था। इसके बाद से ही नेपाल राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। उसी समय से इसके खिलाफ मधेशी आंदोलनरत हैं।
4. नेपाल सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि किसी भी कीमत पर संविधान संशोधन विधेयक वापस नहीं लिया जाएगा, बल्कि इसे लागू करने के लिए जल्द ही स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

पाकिस्ता न ने किया 24वां संविधान संशोधन:

पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने 24वें कानून संशोधन को पारित कर दिया है। हालांकि विपक्ष लगातार इस बाबत सरकार पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का आरोप है कि पनामागेट मामले में फंसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सजा से बचाने के मकसद से ही यह संशोधन किया गया है। दरअसल, इस कानून के नेशनल असेंबली द्वारा पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कोर्ट से मिली सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार मिल जाएगा।

क्या है?

1. पनामागेट कांड में नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए इसकी सुनवाई शुरू की है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नवाज को इस मामले में सजा जरूर होगी इसी सजा से बचने के लिए सरकार ने विपक्ष की सभी मांगों को दरकिनार कर इस तरह का संशोधन कराया है।
2. नेशनल असेंबली में इस संशोधन को पीटीआई समेत पीपीपी ने जबरदस्त विरोध किया है। वहीं एमक्यूएम ने इसका समर्थन करते हुए कहा है कि सजा मिलने की सूरत में पीएम को तय समय के अंदर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील का अधिकार होना चाहिए।
3. एमक्यूएम नेता डॉक्टर आरिफ अल्वी कहना है कि पीएम को सात दिनों के अंदर सजा के खिलाफ अपील करने का अधिकार होना चाहिए, जबकि उस अपील पर साठ दिनों कोर्ट का फैसला हो जाना चाहिए।

चीन ने इलेक्ट्रोनिक टोही पोत लांच किया:

चीन की नौसेना ने एक नया इलेक्ट्रोनिक टोही पोत लांच किया है। लांच किया गया अत्याधुनिक पोत हर मौसम में विभिन्न लक्ष्यों पर लगातार नजर रखने में सक्षम है। बीजिंग ने दक्षिण चीन सागर में अपना दबाव बढ़ाने के लिए बेड़े का विस्तार किया है।

क्या है?

1. क्विंगडाओं में नया पोत सीएनएस कैयांगशिंग या मिजार को लांच किया गया। यह पोत उत्तरी समुद्री बेड़े को सौंपा गया है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के पास अब छह इलेक्ट्रोनिक टोही पोत हो गए हैं।

> ***कैसा है नया टोही पोत?:***
>
> 1. कैयांगशिंग 815ए श्रेणी का इलेक्ट्रोनिक टोही पोत है।
> 2. इसकी कुल विस्थापन क्षमता 6000 मिट्रिक टन है।
> 3. इस पोत की अधिकतम गति 20 नॉट या 37 किलोमीटर प्रति घंटा है।
> 4. इसमें तीन छोटे कैलिबर के नौसैनिक तोप भी लगे हैं।

2. अमेरिका और रूस जैसे कुछ ही देश इस तरह के उन्नत पोत तैयार कर सकते हैं। अमेरिका के पास ऐसे 15 पोत हैं और चीन इस लिहाज से बहुत पीछे है।
3. पीएलए की नौसेना ने भी अपने मीडिया आउटलेट पर सभी छह इलेक्ट्रोनिक टोही पोतों की जानकारी सार्वजनिक की है। सभी पोतों की क्षमता और कार्यप्रणाली का ब्योरा दिया है। इससे पहले पीएलए नौसेना ने अपने जासूसी पोतों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की थी।

अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों में बढ़ोतरी:

अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों में बढ़ोतरी को देखते हुए अमेरिका के इलीट मरीन कमांडो एक बार फिर से वहां जाएंगे और अफगान बलों को लड़ाई के लिए प्रशिक्षित करेंगे। तीन सौ मरीन कमांडो की टुकड़ी फरवरी में हेल्मंड प्रांत में पहुंचेगी।

क्या है?

1. ये कमांडो सन 2014 में नाटो की फौजों की अफगानिस्तान से वापसी के निर्णय के तहत अमेरिका आए थे लेकिन बदले हालात में इन्हें फिर से वहां जाना पड़ेगा। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले के बाद कार्रवाई के लिए सन 2001 में पहली बार मरीन कमांडो अफगानिस्तान गए थे।
2. हेलमंड प्रांत में इनकी बड़ी तैनाती थी क्योंकि यह इलाका अफीम की खेती के लिए बदनाम है, जिससे तालिबान को आर्थिक मदद मिलती है।
3. राष्ट्रपति ओबामा प्रशासन ने थोड़े से सैनिकों को छोड़कर बाकी को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला किया था।
4. लेकिन अफगानिस्तान में अभी भी 8,400 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। हेलमंड में मरीन कमांडो की टुकड़ी इसके अतिरिक्त होगी। यह घोषणा मरीन कॉर्प्स ने की है।

CPEC के लिए चीन ने सौंपे दो शिप:

चीन ने पाकिस्तान के बीच तैयार हो रहे आर्थिक कॉरिडोर की सुरक्षा के नाम पर दो पोत पाकिस्तान को सौंपे हैं। इसके अलावा भी वह दो अन्य पोत आने वाले समय में पाकिस्तान को सौंपेगा। इसके जरिए वह इस आर्थिक कॉरिडोर की ज्वाइंट सिक्योरिटी करेगा। इनकी तैनाती ग्वादर बंदरगाह पर की जाएगी। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल अरिफुल्लाह हुसैनी ने इन दो पोतों को रिसीव किया। इनका नाम पीएमएसएस हिंगोल और पीएमएसएस बसोल है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. इनका नाम चीन की दो नदियों पर रखा गया है। यह दोनों पोत अब से पाकिस्तान नौसेना का हिस्सा होंगे। इन दो पोतों के मिल जाने से पाकिस्तान नेवी को समुद्री सुरक्षा में और मजबूती मिलेगी।
2. आर्थिक कॉरिडोर के लिए पाकिस्तान ने एक नई डिवीजन का भी गठन किया है। यहां की सुरक्षा और ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा का दायित्व इसके ही जिम्मे होगा। ग्वादर पोर्ट की सुरक्षा का जिम्मा पहले ही सेना की नई डिवीजन के हाथों में सौंप दिया गया है। इस नई डिवीजन का गठन पूर्व सेना प्रमुख राहिल शरीफ के कार्यकाल में ही कर लिया गया था।
3. दोनों देशों के बीच बन रहे इस आर्थिक कॉरिडोर पर करीब 54 बिलियन डॉलर की लागत का अनुमान है। इसके जरिए चीन सिल्क रूट को दोबारा सामने लाने की कोशिश कर रहा है। इस रूट के जरिए वह काशगर और ग्वादर से सीधे तौर पर जुड़ना चाहता है। इसके लिए वह इस रूट पर तेजी से सड़क और रेल परिवहन के साथ साथ ऑप्टीकल फाइबर और पाइपलाइन का निर्माण कर रहा है।
4. गेम चेंजर साबित होगा सीपीईसी।
5. पाकिस्तान और चीन के बीच बन रहा यह आर्थिक कॉरिडोर पूरे क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा। इस कॉरिडोर का फायदा बलूचिस्तान को भी समान रूप से मिलेगा और वहां पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, साथ ही हजारों युवाओं को काम मिल सकेगा।

आर्थिक

बजट स्थगन याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार:

उच्चतम न्यायालय ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले आम बजट पेश नहीं किए जाने संबंधी याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि समय आने पर विचार किया जाएगा।

क्या है?

1. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक फरवरी को पेश किए जाने वाले बजट पर रोक लगाने की मांग की थी। उनका कहना था कि चार फरवरी से आठ मार्च तक यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं।
2. इससे पहले केंद्र सरकार बजट में लोकलुभावन घोषणाएं कर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर सकती हैं।
3. अपील पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर ने कहा, 'इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। हम उचित समय आने पर कानून के मुताबिक विचार करेंगे, लेकिन अभी नहीं।'
4. इससे पहले विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य चुनाव आयुक्त से भी मिला था और बजट पेश करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इतना ही नहीं विपक्ष राष्ट्रपति से भी इसको लेकर गुहार लगा चुका है।
5. मामले पर भाजपा का कहना है कि बजट पेश करना सरकार का संवैधानिक दायित्व है और यह किसी राज्य से जुड़ा नहीं है।

भारत और कजाखस्तान ने डीटीएसी में पर हस्तापक्षर किए:

भारत और कजाखस्तानन ने दोनों देशों के बीच मौजूदा दोहरा कराधान निवारण संधि (डीटीएसी) में संशोधन के लिए एक प्रोटोकॉल पर हस्तादक्षर किए, जिस पर इससे पहले 9 दिसंबर, 1996 को दस्ताखत किए गए थे। आय पर लगने वाले करों के संदर्भ में दोहरे कराधान को टालने और वित्तीय अपवंचन की रोकथाम के उद्देश्य से इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रोटोकॉल की विशेष बातें निम्नलिखित हैं:

1. प्रोटोकॉल में कर संबंधी मसलों की जानकारी के कारगर आदान-प्रदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तेर पर मान्यप मानकों का उल्लेख है। इसके अलावा, कर संबंधी उद्देश्यों से कजाखस्तान से प्राप्तत होने वाली सूचनाओं को कजाखस्तान के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्यश विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है। इसी तरह कर संबंधी उद्देश्यों से भारत से प्राप्त होने वाली सूचनाओं को भारत के सक्षम प्राधिकरण की अधिकृत अनुमति से अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसियों से साझा किया जा सकता है।
2. प्रोटोकॉल में 'लाभ की सीमा' से जुड़ा अनुच्छेद है, ताकि डीटीएसी का दुरुपयोग रोका जा सके और इसके साथ ही कर अदायगी से बचने अथवा इसकी चोरी के विरुद्ध बनाए गए घरेलू कानून और संबंधित उपायों को लागू किए जाने की अनुमति दी जा सके।
3. ट्रांसफर प्राइसिंग मामलों में आर्थिक दोहरे कराधान से राहत देने के उद्देश्य से भी इस प्रोटोकॉल में कुछ अन्य विशिष्टम प्रावधान किए गए हैं। यह करदाताओं के अनुकूल कदम है।
4. प्रोटोकॉल में एक तय सीमा के साथ सर्विस संबंधी पीई (स्थोयी प्रतिष्ठान) के लिए भी प्रावधान हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

5. इसमें इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि पीई के खाते में जाने वाले लाभ का निर्धारण संबंधित उद्यम के कुल लाभ के संविभाजन के आधार पर किया जाएगा।

'एसईजेड इंडिया' एप लॉन्च किया गयाः

वाणिज्य सचिव द्वारा 'एसईजेड इंडिया' नामक एक मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। वाणिज्य विभाग के एसईजेड प्रभाग ने अपनी व्यापक ई-गवर्नेंस पहल अर्थात एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) के लिए मोबाइल एप का विकास किया है। वाणिज्य सचिव ने एप लॉन्च किया तथा कहा कि यह एप एसईजेड इकाईयों और डेवलपरों को सूचनाओं को आसानी से प्राप्त करने तथा एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम पर उनकी लेनदेन को ट्रैक करने में सहायता प्रदान करेगा। अब एसईजेड डेवलपर और इकाईयां एसईजेड ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से अपने लेनदेनों को डिजिटल तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं और एसईजेड इंडिया मोबाइल एप के जरिए उसकी स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। यह एप एसईजेड डेवलपरों, इकाईयों, अधिकारियों एवं अन्य लोगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने हेतु एंड्रायड प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इस एप के चार खंड हैं: एसईजेड इनफॉरमेशन, एसईजेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ट्रेड इनफॉरमेशन एवं कॉन्टेक्ट डिटेल्स।

इन चारों खंडों की मुख्य विशेषताएंः

1. एसईजेड इनफॉरमेशन-यह एसईजेड अधिनियम 2005, एसईजेड नियम 2006, एमओसीआई परिपत्र, एसईजेड एवं इकाईयों के विवरण आदि का एक सार-संग्रह है। यह उपरोक्त सभी पहलुओं पर व्यापक ताजा विवरण प्रस्तुत करता है।
2. ट्रेड इनफॉरमेशन-यह प्रावधान विदेश व्यापार नीति, प्रक्रियाओं की लघु पुस्तिका, ड्युटी कैलकुलेटर, सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क अधिसूचनाएं एवं एमईआईएस दरों जैसी महत्वपूर्ण सूचना/टूल्स तक पहुंच प्रदान करता है।
3. कॉन्टेक्ट डिटेल्स-इस खंड में सभी विकास आयुक्त कार्यालयों, डीजीएफटी, डीजी प्रणाली, डीजीसीआई एवं एस तथा एसईजेड ऑनलाइन के संपर्क विवरण दिए गए हैं।
4. एसईजेड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन-यह एक गतिशील उपविकल्प सूची है जो एंट्री बिल/शिपिंग बिल प्रोसेसिंग स्टेटस को ट्रैक करता है तथा उनका सत्यापन भी करता है। यह एप आईसीईजीएटीई की ईडीआई प्रणाली में 'एंट्री बिल/शिपिंग बिल' के समेकन तथा प्रोसेसिंग के स्टेटस को ट्रैक करने में आयातकों/निर्यातकों की मदद भी करता है।

राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान, 2016-17:

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वायन मंत्रालय के केन्द्री य सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ने वित्त वर्ष 2016-17 के लिए स्थिर मूल्यों (2011-12) और वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय आय के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं।

क्या है?

1. वर्ष 2016-17 में स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी अथवा सकल घरेलू उत्पामद (जीडीपी) के बढ़कर 121.55 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2015-16 में जीडीपी का अंतिम अनुमान 113.50 लाख करोड़ रुपये आंका गया था, जो 31 मई 2016 को जारी किया गया था। वर्ष 2016-17 में जीडीपी वृद्धि दर 7.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2015-16 में जीडीपी वृद्धि दर 7.6 फीसदी आंकी गई थी।
2. जिन क्षेत्रों ने 7.0 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि दर दर्ज की है उनमें 'लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्यी सेवाएं', 'वित्तीय, अचल संपत्ति एवं प्रोफेशनल सेवाएं' और 'विनिर्माण' शामिल हैं।
3. 'कृषि, वानिकी एवं मत्स्यी पालन', 'खनन एवं उत्खनन', 'विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्यू उपयोगी सेवाओं', 'निर्माण' और 'व्यापार, होटल, परिवहन, संचार एवं प्रसारण से जुड़ी सेवाओं' की वृद्धि दर क्रमशः 4.1, (-) 1.8, 6.5, 2.9 और 6.0 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है।
4. वर्ष 2016-17 के दौरान वास्तविक रूप में (2011-12 के मूल्यों पर) प्रति व्यक्ति आय के बढ़कर 81805 रुपये हो जाने की संभावना है, जो वर्ष 2015-16 में 77435 रुपये थी। वर्ष 2016-17 के दौरान प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 5.6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष 6.2 फीसदी थी।
5. वर्ष 2016-17 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) के बढ़कर 151.93 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच जाने की संभावना है, जो वर्ष 2015-16 में 135.76 लाख करोड़ रुपये आंकी गई थी। यह 11.9 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाती है।

हिसाब-किताब नहीं देने पर NGO के खिलाफ क्रिमिनल केसः

NGO द्वारा पब्लिक मनी का इस्तेमाल करने के बाद उसका ब्यौरा नहीं देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन NGO द्वारा हिसाब का ब्यौरा नहीं दिया गया है उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए और उनके

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 31 मार्च तक हर सूरत में ऐसे NGO का ऑडिट कराएं और अदालत के सामने रिपोर्ट पेश करें।

क्या है?

1. चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि NGO को पब्लिक मनी दी जाती है और ये पैसा जनता का धन है उसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता इसलिए हिसाब-किताब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये भी कहा है कि वह भविष्य में NGO की मान्यता के लिए गाइडलाइंस तय करें और अदालत को इस बारे में अवगत कराए। अदालत ने कहा कि जो भी हलफनामा दिया जाए उसमें जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी की मंजूरी होना चाहिए।
2. सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले सीबीआई की ओर से पेश रिपोर्ट का हवाला देकर बताया गया कि दश भर में कुल 32 लाख 9 हजार 44 NGO रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इनमें से 3 लाख 7 हजार 72 NGO ही रिटर्न फाइल करते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने NGO के ऑडिट की निगरानी के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं होने पर सरकार की खिंचाई की और तब चीफ जस्टिस ने पूछा कि सरकार पब्लिक मनी का हिसाब क्यों नहीं रखती। कोर्ट को बताया गया जो रिटर्न फाइन नहीं करते उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाता है तब कोर्ट ने कहा कि इतना ही काफी नहीं है।
3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि पब्लिक मनी का इस्तेमाल कर रहे NGO की ऑडिट और निगरानी हो। सरकार बड़ी संख्या में NGO को फंड देते हैं और सरकार के पास इसका रेकॉर्ड नहीं है इसकी मंजूरी नहीं दी जा सकती।
4. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह 31 मार्च तक तमाम NGO के अकाउंट का ऑडिट करे और हर हाल में ऑडिट रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने सौंपी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन NGO ने बैलेंसशिट नहीं दी है उन्हें ब्लैक लिस्ट किया जाए और फिर उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए।
5. पांच साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट एम. एल. शर्मा ने महाराष्ट्र के कई NGO के खिलाफ याचिका दायर की थी और गबन का आरोप लगाया था इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले का दायरा बढ़ाते हुए देश भर के NGO के मामले में सीबीआई से जवाब मांगा था।
6. सुप्रीम कोर्ट में दायर CBI के रेकॉर्ड के मुताबिक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के तहत रजिस्टर्ड किये गये 30 लाख NGO में से सिर्फ 3 लाख NGO ही सालाना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दाखिल करते हैं। सीबीआई के मुताबिक कुछ राज्यों में पैसों के लेनदेन को पारदर्शी बनाये रखने के लिए कानून तक नही हैं।
7. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि था आखिर सरकार अपने ही पैसों का हिसाब क्यों नहीं लेती? क्या असल में सरकार में बैठे लोग ही इन पैसों का इस्तेमाल करते हैं? सीबीआई का कहना था कि यूपी में 5 लाख NGO रजिस्टर्ड है जबकि महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। इस मामले में 2011 में एडवोकेट एमएल शर्मा ने PIL दाखिल की थी। PIL में आरोप लगाया गया था कि देश भर में कई NGO में फंड का कथित तौर पर गबन हो रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर, 2013 को सीबीआई से इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था।

भारत-सीईआरटी ने अमेरिका-सीईआरटी के साथ एमओयू:

भारत और अमेरिका ने भारत सरकार के इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीनस्थ इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम (सीईआरटी-इन) और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के बीच एक सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करवाए हैं।

क्या है?

1. यह एमओयू साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव श्रीमती अरुणा सुंदर राजन और भारत में अमेरिका के राजदूत श्री रिचर्ड वर्मा ने आज इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए।
2. उपर्युक्त एमओयू का उद्देश्य हर देश के प्रासंगिक कानूनों, नियमों एवं विनियमों के साथ-साथ इस एमओयू के अनुसार भी साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और संबंधित सूचनाओं का आदान-प्रदान सुनिशित करना है। इस कार्य को समानता, पारस्परिकता और पारस्परिक लाभ के आधार पर मूर्त रूप दिया जाएगा।
3. इससे पहले अमेरिका एवं भारत ने आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और साइबर सुरक्षा के लिए संबंधित देशों की सरकार के जवाबदेह संगठनों के बीच समय पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करने के लिए 19 जुलाई, 2011 को एक एमओयू पर

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

हस्ताक्षर किए थे। संबंधित सूचनाओं को साझा करने और साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए 19 जुलाई, 2011 से ही सीईआरटी-इन और अमेरिका-सीईआरटी के बीच नियमित रूप से आपसी संवाद जारी हैं।

4. साइबर सुरक्षा से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को जारी रखते हुए ही दोनों देशों ने इस एमओयू का नवीकरण किया है।

विज्ञान और तकनिकी

मलेरिया का टीका परीक्षण में सफलः

मलेरिया का एक नया टीका इनसानों पर किए गए पहले चिकित्सकीय परीक्षण में काफी प्रभावी और सुरक्षित पाया गया है। यह टीका आनुवांशिक रूप से संशोधित मलेरिया परजीवियों से तैयार किया गया है। इस टीके को जीओपी3केओ नाम दिया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा, यह इस टीके के इनसानी परीक्षण का पहला चरण है। इसके निर्माण में इस्तेमाल करने के लिए मलेरिया परजीवी को आनुवांशिक रूप से कुछ कमजोर किया गया, ताकि उसकी मारकता कुछ कम हो जाए। उन्होंने कहा, इंसानों पर पहले परीक्षण के तहत 10 स्वस्थ प्रतिभागियों को यह टीका दिया गया। उन्हें यह टीका एक नियंत्रित माहौल में संक्रमित मच्छरों के जरिये दिया गया।

क्या है?

1. परीक्षण के नतीजों ने दर्शाया कि प्रतिभागियों के शरीर ने टीके को अच्छे से सहन किया और इसने उनके प्रतिरक्षा तंत्र को पर्याप्त रूप से उत्तेजित किया। जबकि चूहों पर परीक्षण के दौरान इस टीके ने उन्हें मलेरिया के संक्रमण से पूरी तरह सुरक्षित रखा।
2. अमेरिका के सेंटर फॉर इन्फेक्सियस डिजीज रिसर्च के शोधकर्ताओं ने यह टीका तैयार करने के लिए मलेरिया परजीवी प्लाजमोडियम फैलिसिपैरम से तीन जीन हटा दिए। ये जीन लिवर को संक्रमित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। इन जीन से रहित मलेरिया परजीवी इस बीमारी का मुकाबला करने में सक्षम हो गया।
3. परीक्षण के दौरान आनुवांशिक रूप से संशोधित परजीवियों (जीएपी) ने प्रतिभागियों के लिवर में मलेरिया परजीवियों के विकास को रोक दिया।
4. मलेरिया परजीवी पहले व्यक्ति के लिवर को और फिर खून को संक्रमित करता है। खून में संक्रमण के बाद ही मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। लेकिन इस टीके ने लिवर में संक्रमण को रोककर प्रतिभागियों के खून को भी संक्रमित नहीं होने दिया। मुख्य शोधकर्ता सेबस्टियन मिकोलैज्क ने कहा, इनसानी परीक्षण में मिली यह सफलता मलेरिया के प्रभावी टीके को विकसित किए जाने की दिशा में एक अहम मुकाम है।

बीमारी के कारण

1. प्लाजमोडियम परजीवियों के कारण होता है मलेरिया
2. मच्छर के काटने से इनसान तक पहुंचते हैं ये परजीवी
3. संक्रमण के बाद सबसे पहले लिवर पर पड़ता है असर
4. लिवर के बाद मरीज के खून तक पहुंच जाता है संक्रमण

5. वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के जेम्स कबलिन ने कहा कि मलेरिया का यह सबसे उन्नत चिकित्सकीय टीका मलेरिया परजीवी के हिस्से से तैयार किया गया है और केवल आंशिक रूप से (लिवर संक्रमण से) सुरक्षा देता है। लेकिन इसने जो क्षमता दिखाई है उससे मलेरिया संक्रमण के विश्व व्यापी खतरे से निपटने में प्रभावी मदद मिलने की संभावना है। अब इस टीके का दूसरा इनसानी परीक्षण किया जाएगा। यह अध्ययन जर्नल साइंस ट्रांजिशनल मेडिसिन में छपा है।

क्यों है जरूरत?

1. 50 फीसदी वैश्विक आबादी पर है मलेरिया का जोखिम
2. 7.4 अरब से अधिक है दुनिया की आबादी फिलहाल
3. 2.14 करोड़ लोग संक्रमित हुए थे 2015 में
4. 5.84 लाख मौतें हुई इस बीमारी के कारण

10वीं के स्टूडेंट ने बनाया एंटी लैंडमाइंस ड्रोनः

वाइब्रेंट गुजरात समिट में सभी की आंखें 14 साल के हर्षवर्धन जाला को ढूंढ रहीं थीं। इसकी वजह भी थी क्योंकि हर्ष ने एक उन्नत ड्रोन डिजाइन किया है जिसे लेकर सरकार ने उनके साथ 5 करोड़ का समझौता किया है। हर्षवर्धन की इस उपलब्धि की वाइब्रेंट गुजरात समिट में खूब चर्चा रही और वहां मौजूद लोगों ने हर्ष के काम की खूब सराहना भी की।

क्या है हर्ष के इस ड्रोन की खासियतः

1. हर्ष ने गुजरात सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ मिलकर ऐसे ड्रोन तैयार करने के लिए करार किया है जिसकी मदद से युद्ध के मैदानों में लगे लैंड माइंस का पता लगाया जा सकेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. ये ड्रोन न सिर्फ लैंड माइंस का पता लगाएगा बल्कि उन्हें निष्क्रिय करने में भी सक्षम होगा। बता दें कि हर्ष अभी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और ड्रोन प्रोडक्शन के अपने बिजनेस प्लान पर कम कर रहे हैं।
3. हर्षवर्धन ने बताया कि उन्होंने लैंडमाइन का पता लगाने वाले ड्रोन के नमूने पर 2016 में ही काम शुरू कर दिया था और बिजनेस प्लान भी बनाया था।
4. हर्ष के मुताबिक, 'ऐसा ड्रोन बनाने का आइडिया उस समय आया जब मैं टेलिविजन देख रहा था और पता चला कि हाथ से लैंडमाइन को निष्क्रिय करते वक्त बड़ी संख्या में सैनिक जख्मी होकर दम तोड़ देते हैं।' उन्होंने अब तक ड्रोन के नमूने पर करीब 5 लाख रुपये खर्च किया है। पहले दो ड्रोन के लिए उनके अभिभावक ने करीब 2 लाख रुपये खर्च किया जबकि तीसरे नमूने के लिए राज्य सरकार की ओर से 3 लाख रुपये की मदद की गई है।
5. 'ड्रोन में मकैनिकल शटर वाला 21 मेगापिक्सल के कैमरे के साथ इंफ्रारेड, आरजीबी सेंसर और थर्मल मीटर लगा है। कैमरा हाई रिजॉलूशन की तस्वीरें भी ले सकता है।'
6. ड्रोन जमीन से दो फीट ऊपर उड़ते हुए आठ वर्ग मीटर क्षेत्र में तरंगें भेजेगा। ये तरंगें लैंड माइंस का पता लगाएंगी और बेस स्टेशन को उनका स्थान बताएंगी।
7. ड्रोन लैंडमाइन को तबाह करने के लिए 50 ग्राम वजन का बम भी अपने साथ ढो सकता है। बता दें कि हर्ष के पिता प्रद्यु मनीष जाला नरोडा की एक प्लास्टिक कंपनी में अकाउंटेंट हैं जबकि उनकी माता निशाबा जाला गृहिणी हैं।

ई-कोली बैक्टीरिया से बनाया बायो केमिकल:

भारतवंशी समेत वैज्ञानिकों के एक दल ने ई-कोली बैक्टीरिया की कोशिका श्रृंखला की मदद से खास बायो केमिकल सेरीन बनाने में सफलता हासिल की है। सेरीन उन 20 अमीनो एसिड में से है, जो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके अलावा पानी में आसानी से घुल जाने के कारण दवाओं और सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में भी इसका इस्तेमाल होता है।

क्या है?

1. डेनमार्क के नोवो नोर्डिक्स फाउंडेशन सेंटर फॉर बायोसस्टेनेबिलिटी के शोधकर्ताओं ने कहा कि इस प्रक्रिया में सतत् रूप से और कम लागत में सेरीन बनाना संभव होगा।
2. प्रोफेसर एलेक्स टोफ्टगार्ड नीलसन ने कहा, 'यह एक अनोखी खोज है। इससे साबित होता है कि हम कोशिकाओं का इस्तेमाल लगातार सेरीन बनाने में कर सकते हैं। अब तक लोग इसे असंभव मानते रहे हैं।'
3. बैक्टीरिया की मदद से रसायन बनाने की प्रक्रिया में वैज्ञानिकों ने रोबोट की भी सहायता ली।
4. शोधकर्ता हिमांशु मूंदड़ा के मुताबिक कोशिकाओं के विकास पर हर पल नजर रखनी होती है।
5. विकास के खास क्रम पर कोशिकाओं की जगह बदलनी होती है। इस काम में विशेषरूप से प्रयोगशाला के लिए तैयार रोबोट की मदद ली जाती है। ई-कोली बैक्टीरिया मनुष्य एवं अन्य जीवों की आंत में पाए जाते हैं। आमतौर पर ये बैक्टीरिया घातक नहीं होते हैं।

मच्छर पर नहीं परजीवी पर निर्भर है मलेरिया:

मलेरिया के प्रसार को लेकर नई जानकारी सामने आई है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मलेरिया का प्रसार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि मच्छर ने कितनी बार काटा बल्कि यह उस मच्छर में मौजूद परजीवियों की संख्या पर निर्भर करता है। इस शोध के आधार पर मलेरिया के टीके बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

क्या है?

1. लंदन के इंपीरियल कॉलेज के शोधकर्ताओं ने इस शोध को अंजाम दिया है। शोध से इस बात का भी पता लगाना संभव होगा कि मलेरिया का एकमात्र रजिस्टर्ड टीका आरटीएस-एस परीक्षणों में आंशिक रूप से ही प्रभावी क्यों पाया गया? शोधकर्ताओं ने बताया कि मच्छर की लार से परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं।
2. खून से होते हुए परजीवी लिवर में पहुंचते हैं, जहां आठ से 30 दिन के भीतर इनकी तादाद तेजी से बढ़ती है। इसके बाद ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं।
3. अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) से लेकर अन्य वैश्विक संस्थाएं मलेरिया के प्रसार का अनुमान मच्छरों के काटने की औसत संख्या के आधार पर लगाती रही हैं।
4. इस अनुमान में मच्छर में मौजूद परजीवियों की संख्या को ध्यान में नहीं रखा जाता है। नए शोध से इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत सामने आई है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

हज यात्रा की एप लांचः

केंद्र सरकार ने हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है। इसके लिए अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मोबाइल एप लांच किया। इसके जरिये आवेदक फार्म भरने के अलावा ई-पेमेंट से भुगतान भी कर सकेंगे।

क्या है?

1. दक्षिण मुंबई स्थित हज हाउस में मोबाइल एप लांच करते हुए नकवी ने कहा कि पहली बार हज यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल किया जा रहा है। उन्होंने इसे सरकार के 'डिजिटल इंडिया' अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कदम करार दिया।
2. यह एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध हो गया है। अगली हज यात्रा के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है।
3. इसके लिए आवेदन भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आवेदन भेजने की आखिरी तारीख 24 जनवरी है। इस एप में हज के लिए आवेदन, सूचना, पूछताछ और ई-पेमेंट की सुविधा उपलब्ध है।

दिमागी तरंगें याददाश्त को बनाती हैं मजबूतः

वैज्ञानिकों ने पहली बार पता लगाया है कि हमारा दिमाग किसी चीज को स्थायी तौर पर कैसे याद रखता है। उन्होंने पाया है कि दिमाग की कुछ विशेष तरंगें याददाश्त को ठोस बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। शोधकर्ताओं ने उस खास प्रक्रिया की सफलतापूर्वक उस प्रक्रिया की पहचान की, जो हमारे दिमाग की तरंगों को नियमित करता है। उन्होंने पाया कि किसी भी घटना या चीज की याद दिमाग में होने वाली एक खास प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद ज्यादा ठोस हो जाती है। इस प्रक्रिया में दिमाग की 'शार्प वेब रिपल्स' (एसडब्ल्यूआर) नामक लहरदार तरंगें अहम भूमिका निभाती हैं।

क्या है?

1. एसडब्ल्यूआर तरंगों पर दो तंत्रिका कोशिकाओं के जोड़ या तंत्रिका कोशिका और किसी मांसपेशी के जोड़ वाली जगह (सिनेप्स) का नियंत्रण होता है। वास्तव में यह जोड़ दिमाग को यह तय करने में मदद करता है कि उसे किसी अनुभव पर तत्काल क्या प्रतिक्रिया देनी या नहीं देनी है। इस प्रक्रिया को सिनेप्टिक निषेध कहते हैं।
2. एसडब्ल्यूआर दिमाग की तीन प्रमुख तरंगों में से एक है। यह दिमाग के उस हिस्से से निकलती है जिसे हिप्पोकैंपस कहा जाता है। हिप्पोकैंपस याददाश्त के निर्माण से जुड़ा होता है। द इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया के प्रोफेसर पीटर जोनास ने कहा, हमारे अध्ययन ने दिखाया कि सिनेप्टिक निषेध बिल्कुल सटीक समय पर एसडब्ल्यूआर को पैदा करता है।
3. शोधकर्ताओं ने चूहे पर किए गए इस अध्ययन में देखा कि एसडब्ल्यूआर की इस प्रक्रिया के दौरान तंत्रिका कोशिकाओं के जोड़ों पर अस्थायी उत्तेजना या अवरोध पैदा होता है। इसी से किसी याद स्थायी या अस्थायी बनना तय होता है। जब एसडब्ल्यूआर पैदा होती है तब उत्तेजना या अवरोध की आवृत्ति बढ़ जाती है।
4. शोधकर्ताओं ने पाया कि उत्तेजना के समय सिनेप्टिक निषेध ने एसडब्ल्यूआर को नियंत्रित किया। इससे साफ हुआ कि वह एसडब्ल्यूआर का आकार और क्षमता तय करता है। उन्होंने उन तंत्रिका कोशिकाओं को भी पहचाना जो एसडब्ल्यूआर को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होती हैं।

रहस्यमयी रेडियो तरंगों के स्रोतः

धरती पर आने वाली रहस्यमयी रेडियों तरंगों के स्रोत का पता चल गया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट (एफआरबी) के नाम से जाने जानी वाले ये तरंगें तीन अरब प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक छोटी आकाशगंगा से आ रही हैं। इसका पता लगाने वाले खगोलविदों के दल में एक भारतवंशी भी हैं।

क्या है?

1. छह महीने तक अध्ययन करने के बाद 'एफआरबी21102' की उत्पति की गुत्थी खगोलशास्त्रियों ने सुलझाई है।
2. सबसे पहले 2012 में प्यूर्टोरिको स्थित अरसेबो वेधशाला के खगोलशास्त्रियों ने इसे देखा था। बीते चार साल में झिलमिलाहट भरी ऐसी रेडियो तरंगें कई बार दिखाई दीं।

क्या है एफआरबी?

1. एफआरबी बहुत ज्यादा ऊर्जा से भरी रेडियो तरंगें होती हैं। लेकिन, इनकी उम्र बहुत कम होती है।
2. सेकेंड के कुछ हिस्सों में ही ये तरंगे खत्म हो जाती हैं। ये तरंगे इतने कम समय में भी इतनी ऊर्जा पैदा करती हैं, जितनी ऊर्जा पैदा करने में सूर्य को 10,000 साल लग जाएंगे।
3. पहली बार 2007 में ऐसी तरंगों की पहचान हुई थी। उसके बाद से 18 एफएसबी की पहचान हो चुकी है। शुरुआत में माना जाता था कि ये पृथ्वी के नजदीक के अथवा उसकी ही आकाशगंगा से आ रहे हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

3. अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन के एक मल्टी-एंटीना वाले रेडियो टेलिस्कोप से इन तरंगों पर नजर रखकर इसकी सटीक स्थिति के बारे में जानकारी जुटाई गई।
4. कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की प्रमुख शोधकर्ता शामी चटर्जी ने बताया कि एफआरबी के स्रोत और इसकी दूरी का पता चलना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन, इन तरंगों को पूरी तरह समझने के लिए अभी काफी शोध की जरूरत है। चटर्जी ने भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) मद्रास में पढ़ाई की है।

विविध

दुनिया की तीन सबसे खूबसूरत जगहों में आगरा का नाम:

दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल के लिए मशहूर शहर आगरा को 2017 की दुनिया की तीसरी सबसे खूबसूरत जगह माना गया है। एक अमेरिकी अखबार की ओर से 2017 में घूमने लायक दुनिया की 52 चुनिंदा जगहों की लिस्ट प्रकाशित की है, जिसमें आगरा को तीसरे नंबर पर रखा गया है। इस लिस्ट में आगरा के अलावा देश के एक और शहर सिक्किम को भी शामिल किया गया है जिसमें सिक्किम को 17वें नंबर पर जगह दी गई है। यानी देश के सिर्फ दो शहरों का नाम ही इस सूची में शामिल किया गया है।

क्या है?

1. **कनाडा**- दुनिया 52 चुनिंदा स्थानों में कनाडा को दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह माना गया है। कनाडा के बारे में कहा जा रहा है कि इसके ज्यादातर बड़े शहर अपने आप में एक छोटी दुनिया की तरह हैं। यहां पर प्राकृतिक छटा को करीब से देखा जा सकता है।
2. **चिली** (अटाकेमा डेजर्ट) चिली के शांत रेगिस्तान इलाके को दुनिया की दूसरी सबसे खूबसूरत जगह में शुमार किया गया है।
3. **आगरा**-इस रिपोर्ट में आगरा के बारे में कहा गया है कि यहां पर ताजमहल के अलावा और भी कई खूबसूरत जगहें जैसे मुगल म्यूजियम, किला, लखनऊ एक्सप्रेस वे, बगीचे और होटल हैं।
4. **स्विटजरलैंड**-इस लिस्ट में दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत चौथी जगह के रूप में स्विटजरलैंड को माना गया है।
5. **बोस्टवाना:** इस लिस्ट के पांचवे नंबर पर अफ्रीकी देश बोस्टवाना को गया गया है। बोस्वाना में अफ्रीकी वन्य जीवों की पर्याप्त उपलब्धता और यहां के प्राकृतिक माहौल के कारण इसके दुनिया का पांचवी सबसे खूबसूरत जगह माना गया है।

आयकर विभाग को ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2016-17:

आयकर विभाग यह घोषित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि उसे मौजूदा परियोजनाओं में 'वृद्धिपरक नवाचार' श्रेणी में आयकर रिटर्न और अन्यर फॉर्मों की ई-फाइलिंग परियोजना के लिए ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कार 2016-17 के तहत रजत पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में विभाग की उपलब्धियों और मौजूदा पुरस्कार अवधि के दौरान सफल ई-गवर्नेंस कार्यक्रमों में उसके महत्वपूर्ण अभिनव कदमों को ध्या्न में रखते हुए दिया गया है। आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग परियोजना को वर्ष 2007-08 में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय पुरस्कारों के तहत रजत पुरस्कार पहले ही प्राप्त हो चुका है। आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग परियोजना के तहत विभाग के अभिनव कदम निम्नपलखित हैं:

1. इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) की शुरुआत करना-जुलाई 2015 में शुरू किये गये इस अभिनव कदम से लोग ईवीसी का उपयोग करते हुए आयकर रिटर्न एवं अन्यर फॉर्मों का इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन सुनिश्चित कर सकते हैं। लोग आधार ओटीपी का इस्तेमाल करते हुए आधार द्वारा मुहैया कराई जाने वाली थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण सेवाओं अथवा नेट बैंकिंग, एटीएम, बैंक खाते के पुष्टिकरण का उपयोग करते हुए बैंकों द्वारा प्रमाणीकरण या डीमैट खाते के पुष्टिकरण का उपयोग करते हुए सिक्योरिटी डिपोजिटरीज के जरिये ईवीसी को प्राप्टट कर सकते हैं, जिसे रिटर्न दाखिल करने के बाद दर्ज किया जा सकता है ताकि इस प्रक्रिया को सत्यापित एवं पूरा किया जा सके।
2. ई-फाइलिंग वॉल्टा का उपयोग करते हुए करदाता के खाते को सुरक्षित करना-इस अभिनव कदम का उद्देश्य ईवीसी अवधारणा से लाभ उठाते हुए करदाता के 'माई एकाउंट' पर लॉग-इन की प्रक्रिया के प्रमाणीकरण में एक और स्तर को जोड़ना और पासवर्ड को फिर से सेट करना है।

प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड:

भारतीय-अमेरिकियों डॉक्टर भरत बरई और डॉक्टर संपत शिवांगी को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड के लिए चुना गया है। दूसरे देशों में रहने वाले भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के आखिरी दिन नौ जनवरी को बेंगलुरू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों को सम्मानित करेंगे। दुनियाभर के भारतीय मूल के लोग इस तीन दिवसीय कार्यक्रम के लिए एकत्रित हुए हैं। इस प्रतिष्ठित सम्मान के विजेताओं की अब तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भारत सरकार ने प्राप्तकर्ताओं को पिछले सप्ताह इस आशय की जानकारी दी।
2. शिकागो में रहने वाले बरई ने वर्ष 2014 में न्यूयॉर्क में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। मिसिसिपी में रहने वाले शिवांगी ने सांसदों के जरिये भारत-अमेरिकी संबंधों को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभायी है।
3. वर्ष 2003 में विदेश मंत्रालय ने इस पुरस्कार की शुरुआत की थी।
4. अब तक विदेशों में बसे 28 भारतीयों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

स्टैण्डर्ड टाइम के अविष्कारक को किया गया याद:

गूगल ने दुनियाभर के लिए मानक समय ईजाद करने वाले कनाडाई अविष्कारक स्टैनफोर्ड फ्लेमिंग को उनकी 190वीं जयंती पर एक डूडल बनाकर याद किया है। वह स्कॉटिश मूल के थे। गूगल ने अपने बयान में कहा, 'आज का डूडल फ्लेमिंग की 190वीं जयंती पर उनकी विरासत को दशार्ता है।' ऐसा माना जाता है कि 1876 में गलत समय सारिणी मुद्रित होने के कारण आयरलैंड में फ्लेमिंग की ट्रेन छूट गई थी, जिसके बाद उनके मन में मानक समय इजाद करने का शानदार विचार आया।

क्या है?

1. फ्लेमिंग का जन्म स्कॉटलैंड के ककाल्र्डी में 1827 में हुआ था। फ्लेमिंग ने 8 फरवरी, 1879 को रॉयल कैनेडियन इंस्टीट्यूट की एक बैठक में मानक समय का प्रस्ताव रखा था। ग्रीनविच रेखा से शुरुआत करते हुए 15 डिगरी के अंतराल स्थान पर दुनियाभर को 24 समय जोन्स में विभाजित करने की बात कही।
2. उनके प्रस्ताव के बाद 1884 में 'इंटरनेशनल प्राइम मेरिडियन कॉन्फरेंस' आयोजित की गई, जिसमें 25 देश शामिल हुए।
3. इस सम्मेलन में फ्लेमिंग की अंतर्राष्ट्रीय मानक समय प्रणाली को अपनाया गया।
4. फ्लेमिंग ने कनाडा के पैसिफिक रेलवे में अपने कार्यकाल के दौरान इंटरकांटिनेंटल रेलवे के निर्माण में भी मदद की। वह कनाडा का पहला डाक टिकट डिजाइन करने के लिए भी जाने जाते हैं।

लोढ़ा कमिटी के सिफारिशों का असर पीसीबी पर:

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) अपने प्रशासकों के लिए 70 साल की उम्र की सीमा अनिवार्य कर देगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने अधिकारियों पर इस तरह की उम्र सीमा रखने पर विचार कर रहा है। इस समय पीसीबी के अध्यक्ष शहरयार खान हैं, जिनकी उम्र 82 वर्ष है।

क्या है?

1. बोर्ड अधिकारी भी उन अधिकारियों को जिम्मेदारी नहीं देने के बारे में सोच रहे हैं जो इस 70 साल की उम्र सीमा को पार कर गए हैं।
2. बोर्ड ने सभी पूर्व टेस्ट खिलाड़ियों की संभावित उम्मीदवारी बना ली है, जिन्हें भविष्य में टीम के साथ जिम्मेदारी दी जाएगी। पिछले साल इंग्लैंड के दौरे के बाद बोर्ड ने पूर्व कप्तान इंतिखाब आलम के सीनियर टीम के मैनेजर के तौर पर और बोर्ड के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया था, क्योंकि वह 76 वर्ष के थे।
3. बोर्ड ने 68 वर्षीय वसीम बारी को पाकिस्तान के टीम मैनेजर के तौर पर नियुक्त किया। इन चुने गए पूर्व खिलाड़ियों की नियुक्ति बोर्ड चेयरमैन द्वारा मंजूरी के बाद की जाएगी जो 60 या इससे ज्यादा उम्र के हैं।
4. पूर्व खिलाड़ी, जिन्हें विभिन्न टीमों के लिये बतौर मैनेजर नियुक्त किया जाएगा, इकबाल कासिम, हारुन राशिद, तलत अली, मोईन खान, जलालुद्दीन, नदीम खान और इकबाल सिकंदर हैं।

विश्व का पहला नेत्रहीनों के लिए पूर्ण एटलस:

नेत्रहीनों के लिए नक्शे उपलब्ध करवाना आसान तो नहीं है लेकिन इन लोगों के लिए भारत में बड़े स्तर पर नक्शे बनाए गए हैं। देख सकने वाले लोगों के लिए नक्शों का इस्तेमाल भी आसान है, लेकिन दुनिया के लाखों नेत्रहीन लोगों के लिए नक्शे दूर की कौड़ी हैं। देख सकने वाले लोग अब अपने आसपास की कॉफी शॉप या मेट्रो स्टेशन का पता लगाने के लिए अपने स्मार्टफोनों में दिए नक्शों का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। नेत्रहीनों की नक्शों तक पहुंच लगभग न बराबर थी लेकिन अब भारत में दृष्टि संबंधी दोषों का सामना करने वाले लगभग 2.8 करोड़ लोगों के लिए यह स्थिति बदल रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने हाल ही में नेत्रहीनों के लिए एक एटलस जारी किया है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. कोलकाता के नेशनल एटलस एंड थीमैटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ने कई साल के प्रयास के बाद ऐसा अदभुत एटलस बनाया। इसमें नक्शे की बाहरी रेखाएं उभरी हुई हैं। इसमें कागज पर सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके नक्शा बनाया गया है ताकि नेत्रहीन लोग उन्हें महसूस कर सकें। इसे ब्रेल एटलस कहा जाता है।
2. भारत के पूर्व महासवेर्क्षक और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी के मौजूदा कुलपति पृथ्वीश नाग के अनुसार, यह दुनिया के नेत्रहीनों के लिए पहला पूर्ण एटलस है। अन्य वैश्विक पहलों के बारे में उन्होंने कहा कि दुनिया के अधिकतर अन्य प्रयास एकल नक्शे बनाने के रहे हैं लेकिन बड़ी संख्या में बनाए जा सकने वाले पूर्ण एटलस का निमार्ण भारतीय प्रयास के तहत किया गया है और यह दुनिया में अपनी तरह की पहली उपलब्धि है।
3. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनियाभर में 28.5 करोड़ लोगों के नजर संबंधी विसंगति का शिकार होने का अनुमान है। इनमें से 3.9 करोड़ लोग नेत्रहीन हैं। यह बात दुखद है कि दुनिया में नजर संबंधी विसंगति से पीड़ित 90 फीसदी लोगों की आय कम है। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा नेत्रहीन लोग रहते हैं और यह स्थिति दुभार्ग्यपूर्ण है क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि इनमें से तीन चौथाई मामले ऐसे हैं, जिनमें नेत्रहीनता से बचा जा सकता है।
4. कुल 84 पन्नों वाले श्वेत-श्याम एटलस को ए-3 आकार के पन्ने पर बनाया गया है ताकि सारी जानकारी आसानी से समाहित की जा सके। बनर्जी के अनुसार, इस परियोजना पर वर्ष 1997 में काम शुरू हो गया था और उनके दल को एटलस बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेल में दक्षता हासिल करनी पड़ी थी। उन्हें इस बात का दु:ख है कि इस काम में बहुत समय लग गया क्योंकि सरकार ने एनएटीएमओ के कर्मचारियों की संख्या को 500 से घटाकर 150 कर दिया।
5. एटलस सिर्फ अंग्रेजी में ही नहीं बल्कि बंगाली, गुजराती और तेलुगू में भी तैयार किया गया है। इसमें 20 विभिन्न नक्शे हैं, जिनमें भारत के राजनीतिक नक्शे, भौतिक नक्शे और भारत में विभिन्न मिट्टियों के नक्शे हैं। एनएटीएमओ ने ब्रेल एटलस की लगभग 500 प्रतियां प्रकाशित की हैं और इनमें प्रत्येक नक्शे की लागत 1000 रूपए है। इन्हें भारत के नेत्रहीन विद्यालयों में मुफ्त में बांटा जा रहा है। एनएटीएमओ का यह प्रयास कम से कम एक बड़ी सामाजिक जरूरत को पूरा करने की दिशा में प्रयास करता है और भारतीय विज्ञान की ओर से समाज की सेवा का पहलू दिखाता है।

आकास्मिक मौत के आंकड़े में गिरावटः NCRB रिपोर्टः

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014 की तुलना में भारत में होने वाली आकस्मिक मौत के आंकड़े में 8.5 फीसद की गिरावट हुई है। हालांकि आत्महत्या के मामले में 1.5 फीसद की मामूली बढ़त देखी गयी। 2014 में दुर्घटनावश होने वाली मौत की दर 36 फीसद थी जो 2015 में घटकर 32 फीसद हो गयी। 2015 में कुल 4,96,762 ट्रैफिक दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में 94 फीसद सड़क दुर्घटनाएं हुई जिसमें से 84 फीसद में मौत की घटनाएं दर्ज की गयी। ट्रैफिक दुर्घटनाओं के अधिकतम मामले मई माह में शाम 3 बजे से 6 बजे के बीच दर्ज किए गए।

क्या है?

1. सड़क दुर्घटनाओं में तमिलनाडु अव्वल है जिसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ें लगभग एक बराबर हैं। अधिकांश दुर्घटनाएं आवासीय क्षेत्रों में हुई। सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होने वालों में अधिकांश दो-पहिए सवार हैं।
2. 2014 से आत्महत्या की दर 10.8 ही बनी हुई है, हालांकि मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है जो 2014 में 1,31,666 थी बढ़कर 2015 में 1,33,623 हो गयी। अधिकांश आत्महत्या के मामले महाराष्ट्र में देखे गए जिसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। पिछले साल भी ये राज्य टॉप पोजिशन पर थे। प्रत्येक 6 में से एक आत्महत्या का मामला हाउस वाइफ का होता है। देश में होने वाली आत्महत्या के कुल आंकड़ों में से 50 फीसद पारिवारिक समस्या और बीमारी के कारण है।
3. 2005-2015 के दशक में दुर्घटनावश होने वाली मौत के आंकड़े 2014 तक बढ़ते रहे हैं जबकि 2015 के आंकड़े कमी को दर्शा रहे हैं। दूसरी ओर आत्महत्या के मामलों में 2011 तक बढ़त का ट्रेंड देखा गया और फिर 2014 में आंकड़े में कमी आयी लेकिन 2015 में फिर से मामूली बढ़त दिख रही है।

चीन के 2000 साल पुराने नमक कानून में बदलावः

चीन ने 2000 साल पुराने नमक कानून में ढील देनी शुरू कर दी है। बता दें कि गत दो हजार साल से चीन में नमक के कारोबार पर सरकार का एकाधिकार था। चीन की राज्य परिषद की पिछले साल की योजना के अनुसार नए साल में सरकारी विनियामक निजी इकाइयों को नमक बाजार में कारोबार की छूट देने जा रहे हैं। नई व्यवस्था में मौजूदा थोक व्यापारियों को

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

अब अपने निर्धारित इलाकों से बाहर जा कर भी कारोबार करने की अनुमति होगी। वे अपना विज्ञापन अभियान भी चला सकेंगे तथा आधुनिक वितरण नेटवर्क भी शुरू कर सकेंगे।

क्या है?

1. राज्य परिषद की अधिसूचना के अनुसार कीमतों को बाजार पर छोड़ा जाएगा पर इस छूट के बावजूद सरकार नमक के खुदरा मूल्य पर निगाह रखेगी, ताकि कीमतों में ज्यादा उतार चढ़ाव न आए।
2. चीन के शासकों ने सदियों से नमक के उत्पादन और व्यापार पर कड़ा नियंत्रण रखा है। यह व्यवस्था 2,000 वर्ष से भी ज्यादा समय से चल रही है। चीन की मौजूदा साम्यवादी सरकार भी नमक के उत्पादन और कीमतों के लक्ष्य तय करते हैं।
3. देश में एक नमक पुलिस भी है ,जो नमक का निजी स्तर पर उत्पादन करने वालों को सूंघ कर उनका कारोबार बंद करा देती है। चीन अब अपने बाजार को निजी और विदेशी प्रतिस्पर्धा के लिए खोल रहा है।
4. शंघाई के वकील झोउ जियालाई ने कहा कि इस नमक कारोबार में सरकार का एकाधिकार खत्म होना मानकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी कंपनियों का नियंत्रण अब भी बना रहेगा पर उन्हें पहले से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना जरूर करना पड़ेगा।

फोर्ब्स के 'सुपर अचीवर' में भारतीयः

फोर्ब्स ने साल 2017 के 'सुपर अचीवर' की सूची जारी की है। दिलचस्प बात ये है कि इस सूची में भारतीय मूल के 30 लोगों का नाम शामिल है, जोकि अलग-अलग क्षेत्र से हैं। ये वो लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है और विश्व को बदलने में यकीन रखते हैं।

क्या है?

1. ये सुपर अचीवर स्वास्थ्य, विनिर्माण, खेल और वित्त जैसे 20 उद्योग क्षेत्र से हैं।
2. सूची में कुल 600 ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने पारंपरिक सोच को चुनौती दी और उद्यमियों, मनोरंजकों और शिक्षाविदों की नई पीढ़ी के नियमों को फिर से लिखा। इनमें कुछ कर गुजरने का जुनून है।
3. इस सूची में नियो लाइट के सह-संस्थापक विवेक कोप्पार्थी का नाम शामिल है जिनकी उम्र 27 साल है।
4. विवेक ने पीलिया रोग में घर पर इस्तेमाल करने वाला एक छोटा प्रकाश-चिकित्सा उपकरण विकसित किया है।
5. इसके अलावा 27 साल की प्रार्थना देसाई भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन्होंने हावर्ड विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई को बीच में इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह विकासशील देशों में ड्रोन की मदद से लोगों का इलाज करने के लिए एक कार्यक्रम चलाना चाहती थीं।

पांच राज्यों में बजा चुनावी बिगुलः

चुनाव आयोग की ओर से उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव तारीखों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक समर का बिगुल बज उठा है। अब 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच इन पांच राज्यों के 16 करोड़ से अधिक मतदाता 690 सीटों पर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।

क्या है?

1. उत्तर प्रदेश में सात चरण के मतदान 11 फरवरी से शुरू हो कर आठ मार्च तक चलेंगे।
2. जबकि पंजाब और गोवा में सबसे पहले एक-एक चरण के मतदान चार फरवरी को हो जाएंगे। उत्तराखंड में भी एक चरण में मतदान होगा जिसके लिए 15 फरवरी की तारीख तय की गई है।
3. उत्तर-पूर्व के राज्य मणिपुर में चार और आठ मार्च को मतदान होगा। सभी राज्यों के चुनाव नतीजे 11 मार्च को एक साथ घोषित किये जाएंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से बुधवार को इन पांच राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।

कालचक्र से रोकने की खबरों को चीन ने किया खारिजः

बोधगया में आयोजित 34वीं कालचक्र पूजा में शामिल होने से तिब्बतियों को रोकने की खबरों का चीन ने खंडन किया है। चीन की जातीय और धार्मिक समिति के अध्यक्ष झू वेकन ने श्रद्धालुओं को रोकने से इन्कार किया। उन्होंने इस आयोजन को चीन विरोधी विचारों को बढ़ावा देने वाला राजनीतिक कवायद बताया।

क्या है?

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

1. कालचक्र आयोजन समिति के अध्यक्ष कर्मा गेलक युथोक ने बताया था कि चीन के दबाव के कारण करीब सात हजार श्रद्धालु पूजा में शामिल हुए बगैर लौट गए हैं। ब्यूरो ऑफ तिब्बत के उप निदेशक शू झिताओ के हवाले से सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीन से वैध तरीके से जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम है।
2. सरकार ने वापस लौटने के लिए इन पर कोई दबाव नहीं बनाया है और न ही सरकार इस आयोजन में शामिल होने के लिए उन्हें प्रोत्साहित कर रही। उन्होंने कहा कि दलाई लामा की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन का इस्तेमाल तिब्बत की निर्वासित सरकार चीन विरोधी विचारों को हवा देने के लिए करती है।
3. गौरतलब है कि दो जनवरी से शुरू हुई कालचक्र पूजा 14 जनवरी तक चलेगी। पूरी दुनिया से लाखों लोग इसमें भाग ले रहे हैं।

भारत के खिलाफ फिर UN की शरण में पाक:

पाकिस्तान ने अपने आतंरिक मामलों में कथित तौर पर भारत के दखल को लेकर एक डोजियर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को सौंपा। पाकिस्तान ने विश्व निकाय से कहा कि वह भारत पर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने को कहे। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की स्थायी राजदूत मलीहा लोधी ने पाकिस्तान में 'भारत के हस्तक्षेप और आतंकवाद' को लेकर एक डोजियर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटिनियो गुटेरेज को सौंपा। उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का एक पत्र भी गुटेरेज को दिया।

क्या है?

1. गुटेरेज के प्रवक्ता स्टीफन दुजार्रिक ने कहा कि इस बैठक का आयोजन पाकिस्तानी राजदूत के आग्रह पर किया था था। जब उनसे यह पूछा गया कि इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है कि बैठक में किस बारे में चर्चा हुई।
2. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, 'डोजियर में पाकिस्तान में भारतीय हस्तक्षेप और रॉ की दखल और खास तौर पर बलूचिस्तान, एफएटीए और कराची में आतंकवाद के बारे सबूत और अतिरिक्त सूचना है। इससे पहले पाकिस्तान ने अक्तूबर 2015 में तीन डोजियर संयुक्त राष्ट्र को सौपें थे।'
3. पत्र में अजीज के हवाले से कहा गया है कि भारत के राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व के हालिया बयानों से भी पाकिस्तान के प्रति भारत के शत्रुतापूर्ण इरादे जाहिर होते हैं। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से निपटने के वैश्विक अभियान में बड़ा योगदान दिया है और आतंकवाद के खिलाफ उसकी घरेलू लड़ाई में उसे अहम लाभ मिला है।
4. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत की ये गतिविधियां संयुक्त राष्ट्र चार्टर तथा आतंकवाद विरोध से जुड़े संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और आतंकवाद संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है। पाकिस्तान ने जाधव पर अपने यहां 'विध्वंसक गतिविधियों' की साजिश रचने का आरोप लगाया है। जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि जाधव नौसेना में था लेकिन भारत ने सरकार के साथ उसका कोई संबंध नहीं है।

स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती:

देशभर में 12 जनवरी 2017 को राष्ट्र की प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। हम महान स्वामी विवेकानंद को नमन करते हैं और उनके शक्तिशाली विचारों और आदर्शों को याद करते हैं जो आज भी पीढ़ियों के मार्गदर्शन का काम कर रहा है। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर देश में युवा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका के शिकागो में सन् 1893 में आयोजित विश्व धर्म संसद में दुनिया के सभी धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच विवेकानंद ने जो भाषण दिया था आज भी उन्हें उसके लिए याद किया जाता है। इस भाषण के जरिए विवेकानंद ने भारत की अतुल्य विरासत और ज्ञान का डंका बजा दिया।

ऐतिहासिक भाषण का कुछ अंश:

1. ब्रह्माण्ड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वह हमीं हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है।
2. उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य ना प्राप्त हो जाये।
3. यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता, तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता।
4. वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वह केवल त्रुटी जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटी यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये काम नहीं कर सकते।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)**

5. कभी मत सोचिये कि आत्मा के लिए कुछ असंभव है। ऐसा सोचना सबसे बड़ा विधर्म है। अगर कोई पाप है, तो वह यह कहना है कि तुम निर्बल हो या अन्य निर्बल हैं।
6. दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो।
7. पहले हर अच्छी बात का मजाक बनता है, फिर उसका विरोध होता है और फिर अंत में उसे स्वीकार कर लिया जाता है।
8. उठो मेरे शेरो, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो, तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो, तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो, तत्व तुम्हारा सेवक है तुम तत्व के सेवक नहीं हो।
9. जो तुम सोचते हो वह हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे, अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे।
10. पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इन्द्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं।
11. एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमे डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ।
12. संभव की सीमा जानने केवल एक ही तरीका है असम्भव से आगे निकल जाना।

चांद अनुमान से अधिक पुरानाः

पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चांद पहले लगाए गए अनुमान से करीब 14 करोड़ वर्ष अधिक पुराना है। नए अध्ययनों के अनुसार चांद 4.51 अरब वर्ष पुराना है। वर्ष 1971 के अपोलो-14 अभियान के तहत चंद्रमा से लाए गए खनिज तत्व जिक्रोन के विश्लेषण के बाद यह बात निकलकर सामने आई है। चांद की उम्र को लेकर लंबे समय से विवाद रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया-लॉस एंजेल्स (UCLA) के रिसर्चर इसपर अध्ययन कर रहे हैं।

ऐसे हुआ था चंद्रमा का निर्माणः

1. पृथ्वी और थिया के आपस में भयंकर टकराव के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ था। इस भयंकर टक्कर में थिया के टुकड़े हो गए थे जिसका कुछ मलबा अंतरिक्ष में चला गया था और यह एकत्रित हो पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। नये रिसर्च के अनुसार, करीब 60 मिलियन साल पहले सौर मंडल के बाद चंद्रमा का निर्माण हुआ था।
2. हालांकि वैज्ञानिकों को यह नहीं पता कि थिया और पृथ्वी के बीच यह टक्कर क्यों हुआ था। यह निष्कर्ष काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वैज्ञानिकों को और भी घटनाओं की जानकारी मिल सकती है।
3. इसके लिए आठ जिर्कॉन का अध्ययन किया। उन्होंने बताया, जिर्कॉन प्रकृति की बेहतरीन घड़ियां हैं। इनके जरिए जियोलॉजिकल इतिहास व इनकी उत्पत्ति का खुलासा होता है। पृथ्वी और थिया के टक्कर से लिक्विफाइड चंद्रमा का निर्माण हुआ जो बाद में ठोस बना।
4. वैज्ञानिकों का मानना है कि निर्माण के बाद चंद्रमा का अधिकांश सतह मैग्मा से ढक गया था। पहले के अध्ययन में चंद्रमा की उम्र इससे प्राप्त पत्थरों के आधार पर निर्धारित की गयी जो अनेकों टकराव के बाद वहां बिखरी थीं।

ओबामा में धार्मिक स्वतंत्रता दिवस घोषितः

अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देश के नागरिकों से धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ खड़े होने की अपील की है। वार्षिक परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने 16 जनवरी को धार्मिक स्वतंत्रता दिवस घोषित किया है। अमेरिका में हर वर्ष राष्ट्रपति 16 जनवरी को धार्मिक स्वतंत्रता दिवस घोषित करते हैं। ओबामा ने कहा, 'धार्मिक स्वतंत्रता का सिद्धांत वंश, संस्कृति, नस्ल या या धार्मिक विश्वास पर आधारित नहीं है। इससे इतर यह स्वतंत्रता के लिए हमारी साझी प्रतिबद्धता पर आधारित है। अमेरिकी होने के नाते यह हम सबके दिलों में बसता है।' ओबामा ने नागरिकों से ऐसी धर्म के कारण निशाना बनाने वाली राजनीति को नकारने की अपील की। उन्होंने कहा, अमेरिका का हिस्सा होने का मतलब कट्टरता को नकारना और दूसरों के लिए आवाज उठाना है। भले दूसरे की पृष्ठभूमि या आस्था कुछ भी हो। राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की ताकत उसकी विविधता में है। धार्मिक स्वतंत्रता अमेरिकी जीवन की 'आधारशिला' है। यह ऐसा अधिकार है, जिसे छीना नहीं जा सकता।

सक्षम-2017ः

केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री 16 जनवरी, 2017 को नई दिल्ली के सिरी फोर्ट सभागृह में महीने भर चलने वाले कार्यक्रम 'सक्षम-2017' का उद्घाटन किये। सक्षम-2017 (संरक्षण क्षमता महोत्सकव) का उद्देश्य 7 ऊर्जा के किफायती उपकरणों के उपयोग एवं स्वच्छ ईंधनों की तरफ रूख करने के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादकों के विवेकपूर्ण इस्ते माल एवं संरक्षण की दिशा में आम लोगों में जागरुकता का सृजन करना है।

क्या है?

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

1. इस कार्यक्रम का आयोजन पीसीआरए (पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संगठन) एवं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़े अन्य व सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा किया जा रहा है।
2. एक महीने तक चलने वाले अभियान के दौरान, वाणिज्यिक वाहनों के चालकों एवं गृहिणियों, रसोइयों के लिए ईंधन बचाने से जुड़े सरल उपायों को अंगीकार करने से संबंधित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
3. सक्षम-2017 का उद्देश्य पहेली प्रतियोगिता, सक्षम एशियाई साइक्लिंग प्रतियोगिता, दौड़ प्रतियोगिता, कन्सीट जैसे कार्यकलापों तथा देश भर में अन्य गतिविधियों के माध्यम से ईंधन सरंक्षण के लिए विभिन्न उपायों के बारे में शिक्षित करना है।

आर्मी डे मनाया गयाः

इंडियन आर्मी अपना 69वां स्थांपना दिवस मना रही है। 15 जनवरी 1949 में भारतीय सेना पूरी तरह ब्रिटिश सेना से आजाद हो गई थी और फील्ड मार्शल के एम करिअप्पा आजाद भारत के पहले सेना प्रमुख बने थे। भारत और चीन को एशिया की दो महाशक्ति माना जाता है। विश्व की जानी-मानी वेबसाइट ग्लोबल फायरपावर में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत विश्व में चौथे नंबर की शक्तिशाली सेना है। इस लिस्ट में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर रूस और तीसरे नंबर पर चीन है। जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान इस रैकिंग में 13वें स्थान पर है।

सैन्य क्षमता	भारत	चीन
सशस्त्र सेना	1,325,000	2,335,000
रिजर्व सेना	2,143,000	2,300,000
अर्धसैनिक बल (अनुमानित)	1,301,000	6,60,000

वायुसेना की क्षमता	भारत	चीन
एयरक्राफ्ट (सभी)	2086	2942
हेलीकॉप्टर	646	802
लड़ाकू हेलीकॉप्टर	19	200
लड़ाकू विमान (फिक्सड विंग)	809	1385
लड़ाकू विमान	679	1230
ट्रेनर एयरक्राफ्ट	318	352
ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट	857	782
एयरपोर्ट	346	507

थल सेना क्षमता	भारत	चीन
युद्धक टैंक	6464	9150
बख्तरबंद लड़ाकू वाहन	6704	4788
स्वचालित बंदूक वाहन	290	1710
तोपखाने	7414	6246
लांचर रॉकेट प्रणाली	292	1770

नौसेना क्षमता	भारत	चीन
मर्चेंट मरीन शक्ति	340	2030
मेजर पोर्ट	7	15
फ्लीट स्ट्रेंथ	295	714
एयरक्राफ्ट कैरियर	2	1
सबमरीन	14	68
युद्ध-पोत	14	48

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

विध्वंसक	10	32
माइन वारफेयर क्राफ्ट	6	4
पेट्रोल क्राफ्ट	135	138

KSG – **(DELHI VN)** 9717380832, **(DELHI RN)** 9811293743, **(JAIPUR)** 8290800441, **(BHOPAL)** 7509975361, **(PATNA)**